शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in

हिंदी दैनिक

गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 11 | अंक : 241 | गुवाहाटी | गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

थाईलैंड में पीएम मोदी से मिल सकते हैं मोहम्मद यूनुस — पेज 2
जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने बरनाडी नदी के किनारे हलधा से बनिया सुपा... — पेज 3
वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के हित में देशभर में बिल का हो रहा है ... — पेज 5
उत्तर मध्य रेलवे की महिला हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक, पुरुष जिम्नास्टिक... — पेज 7

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

राज्य में पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित

2 व 7 मई को मतदान और 11 को मतगणना

गुवाहाटी (हि.स.)। तमाम अटकलों के बीच असम राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। पंचायत चुनाव के लिए दो चरणों में 2 मई और 7 मई को मतदान होगा। मतगणना 11 मई को होगी। निष्पक्ष चुनाव के लिए संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। बुधवार को गुवाहाटी के पांजाबारी स्थित असम राज्य निर्वाचन आयोग के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में असम के प्रदेश चुनाव आयुक्त आलोक कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार 3 से 11 अप्रैल के बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 12 अप्रैल को होगी और 14 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में दो चरणों में 2 और 7 मई को मतदान होगा। पहले चरण में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेउ, शिवसागर, माजुली, जोरहाट, गोलाघाट, धेमाजी, लखीमपुर, शोणितपुर, बिश्वनाथ, कछार, हैलाकांदी और श्रीभूमि जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में धुबड़ी, दक्षिण सलमारा मनकाचर, ग्वालपाड़ा, बंगाईगांव, बरपेटा, बजाली, नलबाड़ी, कामरूप, कामरूप (मेट्रो), होजाई, नगांव, मोरीगांव और दरंग जिलों में चुनाव होंगे। कुल 18036682 मतदाता (9071264 पुरुष मतदाता, 8965010 महिला मतदाता और 408 अन्य मतदाता) वोट डालने के पात्र होंगे। इस साल मतदाताओं की संख्या 2018 के पंचायत चुनावों से 13.27 प्रतिशत अधिक है, जब कुल मतदाता 15641456 थे। दोनों चरणों के दौरान सुबह 7.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक 25007 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। दो चरणों के मतदान के लिए 1,20,000 मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा। दोनों चरणों की मतगणना 11 मई 2025 को होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होकर प्रक्रिया पूरी होने तक चलेगी। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि दोनों चरणों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल, 2025 को सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 12 अप्रैल, 2025 को सुबह 10.30 बजे से होगी। वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की सूची 12 अप्रैल, 2025 को प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 17 अप्रैल, 2025 को अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित की गई है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 17 अप्रैल 2025 को अपराह्न 3 बजे के बाद प्रकाशित की जाएगी। यदि पुनर्मतदान की कोई तिथि निर्धारित की गई है, तो प्रथम चरण के लिए 4 मई, 2025 तथा दूसरे चरण के लिए 9 मई, 2025 है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए 25,007 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि 11 मई को मतगणना कराई जाएगी। चुनाव की तारीख घोषित होते ही राज्यभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत सरकारी योजनाओं की घोषणाओं पर रोक, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर निगरानी और राजनीतिक दलों के प्रचार पर सख्त निगरानी शुरू हो गई। राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। असम में इस बार पंचायत चुनाव में कुल एक करोड़ 80 लाख 36 हजार 682 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट किया है, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से न छूटे। इस बार पंचायत चुनाव बिना किसी प्रतीक चिह्न के आयोजित होगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से आचार संहिता का पालन करने की अपील की है।

वित्त वर्ष 2025 में बजट उपयोग 86 प्रतिशत तक पहुंचा : सीएम हिमंत

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार का बजट उपयोग 86 प्रतिशत रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि में 80 प्रतिशत था। एक्स पर एक पोस्ट में, शर्मा ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में पिछले वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय में भी लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम वित्त वर्ष 2024-25 का समापन कर रहे हैं, हमें मजबूत राजकोषीय अनुशासन और प्रभावी संसाधन प्रबंधन को दर्शाते हुए महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धियों की रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है। सीएम ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में कुल व्यय लगभग 1,44,617 करोड़ रुपए रहा, जो 86 प्रतिशत बजट उपयोग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2023-24 में कुल व्यय 1,36,317 करोड़ रुपए था, जो 80 प्रतिशत बजट उपयोग को दर्शाता है। शर्मा ने कहा कि 2020-21 में कुल व्यय करीब 80,000 करोड़ रुपए रहा, जिसमें बजट का 65 फीसदी उपयोग हुआ। पूंजीगत व्यय के बारे में उन्होंने कहा कि हमने पिछले वर्ष के 21,509 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय को सफलतापूर्वक बढ़ाकर 25,354 करोड़ रुपए कर दिया है, जो बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, सीएम ने कहा कि राज्य ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत 3,035 करोड़ रुपए के नकद शेष के साथ की है कि -शेष पृष्ठ दो पर

सुप्रभात
खुशी तंदुरुस्ती है, इसके विपरीत उदासी रोग है।
-हेली बर्टन

न्यूज गैलरी

लालू की तबीयत बिगड़ी, एम्स के लिए रवाना

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। दिल्ली एम्स में इलाज की सलाह देते हुए डॉक्टरों ने पटना के राबड़ी आवास में उनका शुरुआती इलाज शुरू किया। 4 बजे लालू को दिल्ली निकलना था। परिजन उन्हें लेकर आवास से निकले। इस दौरान तबीयत ज्यादा बिगड़ने -शेष पृष्ठ दो पर

इसी महीने में होगा भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का एलान

नई दिल्ली। कौन होगा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? यह सवाल लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, अब तक नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं की गई है, और वह अभी भी एक्सटेंशन पर पार्टी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस बीच, खबरें थीं कि भाजपा और आरएसएस (आरएसएस) -शेष पृष्ठ दो पर

मुख्यमंत्री ने जोरहाट में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को जोरहाट के चिन्नमारा में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। 19.98 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह नवनिर्मित सुविधा जिले में कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने के लिए तैयार है। सम्मेलन केंद्र 3,118 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें 120 लोगों के बैठने की क्षमता है तथा यह अनेक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इनमें एक कार्यकारी लाउंज, एक समर्पित मीडिया सम्मेलन हॉल और आरामदायक सुइट केबिन शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। शर्मा ने कहा कि यह सम्मेलन केंद्र जिला प्रशासन और जोरहाट के -शेष पृष्ठ दो पर

खेल महारण 2.0 के राज्य स्तरीय खेल शुरू

गुवाहाटी। असम के खेल एवं युवा कल्याण निदेशालय की पहल खेल महारण 2.0 के राज्य स्तरीय खेल आज इंदिरा गांधी स्टेडियम के सरुसजाई खेल परिसर में आधिकारिक रूप से शुरू हो गए। 2 अप्रैल से 6 अप्रैल, 2025 तक चलने वाले इस आयोजन में हर जिले से 7,098 एथलीट भाग लेंगे। इसका उद्देश्य एक मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और उभरती प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री नंदिता गार्लोसा ने एथलीटों का उत्साहवर्धन किया और खेल विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस कार्यक्रम में उत्तरी कछार स्वायत्त परिषद के सीईएम देबोलाल गार्लोसा, विधायक परमानंद राजबोंगशी और रामेन कलिता, गुवाहाटी नगर निगम के मेयर मृगेन शरणिया भी शामिल हुए। असम ओलंपिक संघ के सचिव, लक्ष्य कुवंर और जेएसडब्ल्यू की खेल प्रमुख, मनीषा मल्होत्रा ने असम के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में इसके महत्व को रेखांकित किया। 7.3 मिलियन से अधिक पंजीकरणों के साथ, यह आयोजन असम के बढ़ते खेल आंदोलन का प्रमाण है। प्रत्येक जिले में कोच और प्रबंधकों सहित कुल 234 प्रतिनिधिमंडल हैं। कबड्डी, साइकिलिंग, तैराकी, फुटबॉल, शतरंज, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स सहित कई विषयों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। -शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर हिंसा : दिल्ली में होने वाली वार्ता से पहले कुकी समूहों ने रखीं शर्तें

इंफाल। मणिपुर में कुकी समूहों ने कुकी-जो और मैतेई समूहों के बीच दिल्ली में 5 अप्रैल को होने वाली वार्ता से पहले तीन पूर्व शर्तें रखी हैं, जिसका उद्देश्य राज्य में चल रहे संकट को हल करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा को समाप्त करने के प्रयास में दो समूहों - इंफाल घाटी स्थित बहुसंख्यक मैतेई और आसपास की पहाड़ियों पर रहने वाले कुकी-जो आदिवासियों के बीच वार्ता का आह्वान किया है। इस संघर्ष में 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कुकी -शेष पृष्ठ दो पर

शोणितपुर के नो-दुआर को मिला राज्य का पहला सह-जिला आयुक्त कार्यालय

नो-दुआर। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को नो-दुआर निर्वाचन क्षेत्र के पहले सह-जिला आयुक्त कार्यालय की आधारशिला रखी। अत्याधुनिक, चार मंजिला इमारत 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। समारोह में बोलते हुए, शर्मा ने सह-जिलों के महत्व पर प्रकाश डाला, जो कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक पहल है जिसने राज्य के शासन ढांचे को नया रूप दिया है। उन्होंने कहा कि उप-जिलों के निर्माण से असम के लोगों को प्रशासनिक लाभ मिला है। नादौर में अब शहरों की तरह ही शासन में आसानी और दक्षता का अनुभव होगा। शर्मा ने असम माला योजना के तहत एक प्रमुख सड़क परियोजना की भी घोषणा की - इटाखुला से तिवारीपाल होते हुए सोतिया डिप्लोंगा तक 20 किलोमीटर का मार्ग, जो स्थानीय विधायक पद्मा हजारिका की लंबे समय से मांग थी। शर्मा ने पुष्टि करते हुए कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इस सड़क का निर्माण इसी वर्ष किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विश्वनाथ के पानपुर रोड में घिलोरीदरी सहायक नदी पर एक नया आरसीसी पुल बनाया जाएगा, जिसके लिए 7 करोड़ रुपए -शेष पृष्ठ दो पर

रतन टाटा की वसीयत

रसोइया-ड्राइवर बना करोड़पति कुत्ते टीटो को मिला 12 लाख

नई दिल्ली। रतन टाटा का नाम सुनते ही भव्यता, सफलता और उदारता मन में उभरता है, लेकिन उनकी वसीयत ने एक और पहलू उजागर किया- जिसमें सादगी और मानवीय मूल्यों की मिसाल पेश की गई। जहां अधिकतर बिजनेसमैन अपनी संपत्ति अपने परिवार के विस्तार में लगे रहते है, वहीं टाटा ने अपने कर्मचारियों, सहयोगियों और यहां तक कि अपने पालतू कुत्ते तक -शेष पृष्ठ दो पर

अमेरिकी कोर्ट ने डोभाल पर लगे आरोप खारिज किए

न्यू यॉर्क। अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल को अदालती दस्तावेज सौंपे जाने के खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के दावे को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि डोभाल को कोई समन या अन्य अदालती दस्तावेज नहीं सौंपे गए। अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने आदेश में कहा कि स्तावेज न तो डोभाल को मिले, न ही उनके होटल स्टाफ या सुरक्षा एजेंटों को सौंपे गए। -शेष पृष्ठ दो पर

वक्फ पर संसद में हुई बहस

गौरव गोगोई ने सरकार पर संविधान कमजोर करने का लगाया आरोप, गृह मंत्री और किरेन रिजिजू ने दिया जवाब

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने दावा किया कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य संविधान को कमजोर करना, अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करना, भारतीय समाज को विभाजित करना और अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करना है। उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से आज लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सत्त पक्ष पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस नेता के दावे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किरेन रिजिजू ने खारिज करते हुए कि सभी दलों की राय को ध्यान में रखते हुए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की चर्चा हुई थी, कांग्रेस नेता ने पलटवार करते हुए -शेष पृष्ठ दो पर

इमरान मसूद बोले- ये संविधान विरोधी, अनुराग ठाकुर ने विधेयक को बताया एक उम्मीद

नई दिल्ली। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के गुटों के सदस्यों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के आरोपों पर भाजपा और एनडीए दलों की तरफ से जवाब दिया गया है। इस दौरान कांग्रेस सांसद और इमरान मसूद ने कहा कि डब्ल्यूएएमएसआई पोर्टल का बार-बार जिक्र हो रहा था...10 साल बहुत लंबा समय होता है। आप 10 साल में सभी संपत्तियों का पंजीकरण नहीं कर सके...आप 10 साल में यह काम नहीं कर सके लेकिन अब आप कहते हैं कि संपत्तियों का पंजीकरण 6 महीने के भीतर करना होगा और -शेष पृष्ठ दो पर

दवा की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ ममता ने की आंदोलन की घोषणा

कोलकाता (हि.स.)। केंद्र सरकार के अधीन नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने 1 अप्रैल से देशभर में 748 आवश्यक दवाओं की कीमतों में वृद्धि को मंजूरी दी है। इस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। ममता ने बुधवार को नवान्न में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि 4 और 5 अप्रैल को राज्य के हर ब्लॉक और वार्ड में तृणमूल कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ सभा -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD,** S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, **Ph. : 94350-48866, 94018-06952**

लोस के बाद रास से भी पारित हुआ आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक

नई दिल्ली (हि.स.)। राज्यसभा ने बुधवार को आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक-2025 चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य देश में आप्रवासन से जुड़े कानूनों को नए सिरे से परिभाषित करना है। विधेयक का उद्देश्य केंद्र सरकार को भारत में प्रवेश करने और यहां से प्रस्थान करने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता और विदेशों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करना है। विधेयक के अधिनियम बनने पर यह विदेशियों और आप्रवास से संबंधित मामलों के वर्तमान के चार अधिनियमों- विदेशियों विषयक अधिनियम-1946, आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम-2000, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 और विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम-1939 का स्थान लेगा। लोकसभा इसे 27 मार्च को पहले ही पास कर चुका है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक-2025 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आज हमारे देश में करीब 1 करोड़ 72 लाख एनआरआई हैं। इतना बड़ा डायसपोरा किसी और देश के पास नहीं है। उन सबके आने-जाने और उनकी सारी चिंताओं के निराकरण के लिए यह विधेयक मोदी सरकार ले कर आई है। राय ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार डराना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार किसी को डराना नहीं चाहती है लेकिन डर उनको होना चाहिए जो भारत में आकर देश के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के मन में डर पैदा होना ही चाहिए। इस विधेयक से एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ेगा, डेटा प्रबंधन की जटिलता समाप्त हो जाएगी। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को समिति को रेफर करने की सलाह दी है लेकिन तीन साल के गहन विचार के बाद गृह मंत्रालय ने इस विधेयक को तैयार किया है। देश की आवश्यकता के अनुरूप किया है। इसके प्रावधानों में भारत में प्रवेश और ठहरने के लिए वैध दस्तावेज को अनिवार्यता कर दी गई है। अप्रवास ब्यूरो पहले से ही काम कर रहा है। यह एकमात्र एजेंसी होगी जो विदेश से आने वाले लोगों का लेखा जोखा रखेगी। अब विदेशी लोगों को एक ही एजेंसी से संपर्क करना होगा। ऐसा प्रावधान कई देशों में है। नित्यानंद राय ने कहा कि कुछ सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मेधावी, विदेशी विशेषज्ञों को रोकना चाह रही है लेकिन सरकार को अपने देश के मेधावी विशेषज्ञों पर गर्व है। इसलिए विदेशी लोग जो देश में आकर भारत के विकास के लिए काम करेंगे उनका विरोध नहीं किया जा रहा है लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छे मन से अगर विदेशी लोग आएंगे तो उनका स्वागत होगा और जो नुकसान पहुंचाएगा उसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान इसका विरोध करते हुए कांग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह विधेयक यह संदेश देता है कि सभी विदेशी *संभावित अपराधी* हैं, जिन्हें भारत को गंभीर संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि यह निचले स्तर के अधिकारियों को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है और इसमें अपील, निगरानी और जवाबदेही के अलावा अन्य बातों के लिए प्रावधानों का अभाव है। प्रस्तावित अधिनियम में भारत में प्रवेश करने, रहने या बाहर निकलने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। विधेयक में सात साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। होटलों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए विदेशियों के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा, ताकि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों पर नजर रखी जा सके।

थाईलैंड में पीएम मोदी से मिल सकते हैं मोहम्मद यूनुस

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से थाईलैंड के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जहां वह बिम्सटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात पहली बार होगी, और इसे लेकर बांग्लादेश की तरफ से आग्रह किया गया था। हालांकि, भारत सरकार ने इस बैठक के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच बैठक की तैयारी चल रही है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिन्हें नोवल शांति पुरस्कार मिल चुका है, सामाजिक उद्यमिता और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अपनी कामयाबी के लिए प्रसिद्ध हैं। वह यूनुस सोशल बिजनेस के संस्थापक हैं, जो विकासशील देशों में सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए काम करता है। बिम्सटेक सम्मेलन का आयोजन दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास और आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक को लेकर कई राजनीतिक और कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात दोनों देशों के बीच सामाजिक और विकासात्मक सहयोग के नए रास्ते खोल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत-बांग्लादेश संबंधों को और मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में मोदी की भेंट नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से भी होगी। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि म्यांमा के सैन्य जुंटा नेता मिन आंग ह्लाइंग शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे या नहीं। म्यांमा में पिछले सप्ताह आए भीषण भूकंप से देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले और अन्य हिस्सों में भीषण तबाही हुई। यह 2018 में नेपाल के काठमांडू में चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के बाद बिम्सटेक नेताओं की प्रत्यक्ष रूप से पहली बैठक होगी।

अरुणाचल में शुरू हो रहा रिवर्स माइग्रेशन
अगले 5 सालों में 25 प्रतिशत वापसी का टारगेट

इटानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फर्स्ट विलेज कॉनसेप्ट का असर दिखने लगा है। ऐसा दावा चंगथन रीजन में रहने वाले लोग कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के सांसद और पर्यटन मामलों के मंत्री पासंग दोरजी सोना ने बताया कि केंद्र सरकार ने भारत के बॉर्डर के गांवो को विकसित करने के लिए वाइब्रेंट विलेज का कानसेप्ट लाया था। उसका असर दिख रहा है। उन्होंने दावा किया कि हाल के दिनों में लगभग 10 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो अपने गांव की ओर वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि इससे गांव का विकास बढा है और पलायन को लेकर लोगों की जो सोच थी उसमें परिवर्तन आया है। पासंग दोरजी ने बताया कि अरुणाचल में आने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इसके नियमों में भी काफी बदलाव किया गया है। उन्होंने दावा किया कि इससे देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा होगा। इसके साथ ही गांव के इलाकों में रोड कनेक्टिविटी पर काफी काम किया गया है, जिसका असर यह है कि सीमावर्ती इलाकों में भी अब आसानी से जाया जा सकता है। पासंग दोरजी ने कहा कि हमारी नई पर्यटन नीति लागू होने के बाद इस बात के आसार हैं कि प्रदेश में पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। इसके साथ ही घरेलू पर्यटकों से इतर यदि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन की बात करें तो इसमें दस गुना वृद्धि की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नई पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। इसके प्राचीन परिदृश्य, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और अद्वितीय जैव विविधता को संरक्षित करना है। पासंग दोरजी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) 2023 में 300 प्रतिशत बढ़कर 4,496 हो गया, जबकि घरेलू पर्यटक आगंतुक (डीटीवी) 2022 में 368.91 प्रतिशत बढ़कर 1.04 मिलियन हो गए।

बशिष्ठ पुलिस ने दो चोरों को पकड़ा, चोरी का सामान बरामद

गुवाहाटी (हिंस)। बशिष्ठ पुलिस ने चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान इनामुल अली उर्फ बाबू (22) और राजीव नाथ उर्फ टीकू (19) के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से चोरी का सामान जब्त कर लिया है। इसके अलावा, एक अन्य अभियान में पुलिस ने गणेशपाड़ा स्थित बाथौ मंदिर के पास, मकान संख्या-15 में विद्या बोड़ो के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान, पुलिस ने विभिन्न ब्रांडों की कुल 95.025 लीटर विदेशी शराब बरामद की।

सीएम ने कई परियोजनाओं के उद्घाटन किए

जोरहाट (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को जोरहाट में 110 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक सम्मेलन केंद्र, वाहन स्वचालित उपयोगिता परीक्षण केंद्र और एक रेलवे ओवरब्रिज शामिल हैं। सम्मेलन केंद्र जिला प्रशासन के साथ-साथ जोरहाटवासियों के लिए विभिन्न आयोजनों में विशेष रूप से सहायक होगा।

अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से एनएच-113 पर यातायात बाधित

इटानगर (हिंस)। भारत-तिब्बत और म्यांमार सीमा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 113 भारी बारिश से कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। जिला प्रशासन ने यात्रियों को रात में सफर न करने और प्रभावित क्षेत्र में किसी भी नुकसान की सूचना देने की अपील की है। राजमार्ग पर यातायात बहाल करने के आपातकालीन उपाय किए जा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि भारी बारिश से राजमार्ग 113 पर अंजॉ जिले के एरोवा-खोपा-हायुलियांग सेक्शन के मोनपानी क्षेत्र में कटाव होने से सड़क पर दरारें आ गई हैं, जिससे आवागमन ठप हो गया है और क्षेत्रीय संपर्क बाधित हुआ है। हायुलियांग की विधायक और महिला एवं बाल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान मंत्री दसांगलू पुल राजमार्ग की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने निवासियों को आश्वासन दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, राजमार्ग की बहाली का कार्य तेजी से चल रहा है। वह जिला प्रशासन और एनएचआईडीसीएल (राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम) के साथ लगातार संपर्क में हैं।

मोदी जी तुम संघर्ष करो... हम तुम्हारे साथ हैं, वक्फ पर समर्थन में उतरीं मुस्लिम महिलाएं

नई दिल्ली। लोकसभा में आज सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। कोई इस विधेयक के पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है। सरकार को सदन में जेडीयू, टीडीपी और जेडीएस जैसे दलों का साथ मिला है। वहीं विपक्षी गठबंधन भी बिल के विरोध में लामबंद है। कांग्रेस ने विधेयक को संविधान के खिलाफ बताया। सपा का कहना है कि बिल का विरोध किया जाएगा। विपक्ष के विरोध के बीच दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अलग तस्वीर सामने आई है। यहां मुस्लिम महिलाएं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के समर्थन में उतरीं। भोपाल में बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहीं मुस्लिम महिलाओं के हाथों में पीएम मोदी के समर्थन वाली तख्तियां थीं। इनमें पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया है। महिलाओं ने नारे लगाए कि *मोदी जी तुम संघर्ष करो... हम तुम्हारे साथ हैं।* दिल्ली में भी वक्फ विधेयक के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं उतरीं। महिलाओं ने तख्तियां पकड़ रखी हैं। इनमें लिखा है कि वक्फ संपत्ति की आमदनी उसके हकदार तक पहुंचाने और वक्फ बोर्ड में महिलाओं व पिछड़े मुसलमानों की हिस्सेदारी देने के लिए मोदी जी का शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश के लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए कि भाजपा ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर उन्हें अपने दोस्तों को देने की शुरुआत कर दी है। वे गुरुद्वारों, मंदिरों और चर्च की संपत्तियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। उधर, सुप्रिया सुले का कहना है कि हम विधेयक को देखेंगे। इस पर चर्चा चल रही है। हम आईएनडीआईए गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन पूरी ताकत के साथ रहेगा। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही है। हमारे सीएम एमके स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। हम इस देश के अल्पसंख्यकों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आईएनडीआईए गठबंधन इस विधेयक के खिलाफ एक साथ खड़ा है।

पृष्ठ एक का शेष

वित्त वर्ष 2025 ...

जो हमें निरंतर वित्तीय स्थिरता और रणनीतिक निवेश के लिए मजबूत स्थिति में रखता है। असम के वित्त मंत्री अजंता नेउग ने 10 मार्च को 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए 2.63 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें जनता, मुख्य रूप से युवाओं और चाय बागान श्रमिकों को नकद प्रोत्साहन की एक श्रृंखला दी गई थी, और अगले साल राज्य चुनावों से पहले वेतनभोगी वर्ग को कर छूट दी गई थी। 620.27 करोड़ रुपए के घाटे के साथ, उन्होंने आम जनता के लिए कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया, लेकिन लगभग 1.5 लाख वेतनभोगियों को अतिरिक्त राहत दी। असम में विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल के दौरान होने की संभावना है, जिससे यह राज्य में हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली दूसरी भाजपा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट बन जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जोरहाट...

लोगों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में काम करेगा। उन्होंने इस अवसर पर परिसर में एक नीम का पौधा भी लगाया। इसके अलावा, सीएम शर्मा ने जोरहाट में असम के दूसरे पूर्ण स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अपना वादा निभाते हुए हम जोरहाट में असम का दूसरा पूर्ण स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र शुरू कर रहे हैं। वाहन फिटनेस में क्रांतिकारी बदलाव - शून्य परेशानी, शून्य भ्रष्टाचार, 100 प्रतिशत स्वचालन। मुख्यमंत्री ने कोमारबोंधा रोड पर रेलवे ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया। सीएम शर्मा ने एक्स पर लिखा कि असम के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इसका मतलब है कि हर दिन लगभग एक पुल और 15 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। जोरहाट का रेलवे ओवरब्रिज इस प्रयास का एक और उदाहरण है। कुल 110.77 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये परियोजनाएं जोरहाट के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मणिपुर हिंसा : दिल्ली में ...

जो काउंसिल (केजेडसी) के अध्यक्ष हेनलियानथांग थांगलेट ने कहा कि पूर्व-शर्तों में उन क्षेत्रों में मैतेई और कुकी के बीच क्रॉस-मूवमेंट को प्रतिबंधित करना शामिल है जहां दूसरा समुदाय बहुसंख्यक है। मंगलवार को कांगपोकपी में आदिवासी एकता समिति (सीओटीयू) द्वारा आयोजित परामर्श बैठक के दौरान ये शर्तें स्थापित की गईं। तीन शर्तें हैं: कुकी-जो-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में मैतेई व्यक्तियों की आवाजाही और इसके विपरीत, सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा। बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए कम से कम छह महीने तक शत्रुता को रोका जाएगा। युद्ध विराम अवधि के दौरान एक संरचित, औपचारिक और सार्थक वार्ता प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

शोणितपुर के नो-दुआर ...

का बजट आवंटित किया जाएगा। जनता की मांग के जवाब में, शर्मा ने सरिद्वार में एक कॉलेज और तुपिया, सरिद्वार और जामुगुरी में स्टेडियमों के निर्माण का संकेत दिया, जिससे स्टेडियमों के केवल निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरक्षित होने की परंपरा टूट गई। उन्होंने बताया कि कॉलेज बनाने से पहले हम आस-पास के हाई स्कूलों में छात्र क्षमता का आकलन करेंगे। अगर यह व्यवहार्य पाया गया तो हम निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। शर्मा ने आश्वासन दिया कि शिक्षा प्राथमिकता बनी रहेगी, उन्होंने कहा कि माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है - शिक्षा का ध्यान *मामा* द्वारा रखा जाएगा। कल्याण के मोर्चे पर, उन्होंने सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान और पीएम-किसान सम्मान निधि योजना आदि को दोहराया। जीवन-यापन की लागत कम करने के लिए सरकार अब राशन कार्ड योजना के तहत मुफ्त चावल के अलावा दाल, नमक और चीनी भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराएगी। शर्मा ने कहा कि असम में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोना चाहिए। आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करते हुए, सीएम शर्मा ने लोगों से डेयरी फार्मिंग और कृषि को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन और खेती जैसे व्यवसाय असम की आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें समृद्ध राज्य बनाने के लिए इन क्षेत्रों को अपनाना चाहिए।

खेल महारण 2.0...

उद्घाटन समारोह में एक भव्य मशाल रिले का आयोजन किया गया, जो एकता और खेल भावना का प्रतीक है। माननीय मंत्री नंदिता गार्लोसा ने मशाल को फरहाना जमान को सौंपकर रिले की शुरुआत की, जिन्होंने इसे नम्रता बर्मन को सौंप दिया। मशाल को प्रमुख खेल हस्तियों ने शिव थापा के पास पहुंचाया, जिन्होंने खेलों की शुरुआत का संकेत देने के लिए औपचारिक मशाल जलाई।

रसोइया-ड्राइवर बना...

के लिए बड़ी धनराशि छोड़ी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के लिए केवल 2500 रखे। रतन टाटा की वसीयत उनके निस्वार्थ प्रेम और कर्मचारियों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने अपने घरेलू सहायकों, ऑफिस स्टाफ और पुराने सहयोगियों के लिए करोड़ों रुपए छोड़े। किसी के कर्ज माफ किए, तो किसी को आर्थिक रूप से सुरक्षित किया। लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को 15 लाख, जबकि अंशकालिक कर्मचारियों को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। टाटा की दरियादिली सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते *टीटो* के लिए 12 लाख की राशि निर्धारित की, ताकि उसकी देखभाल में कोई कमी न हो। रतन टाटा के प्रति कर्मचारियों की निष्ठा का बदला उन्होंने दिल खोलकर दिया। उनके रसोइए रंजन शॉ को 1 करोड़ मिले, जिसमें से 51 लाख का कर्ज माफ किया गया। बटलर सुब्बैया कोनार को 66 लाख की सौगात दी गई, जिसमें से 36 लाख का कर्ज माफ हुआ। उनकी सचिव डेलनाज गिल्डर को भी 10 लाख मिले। टाटा ने अपने युवा कार्यकारी सहायक शांतनु नायडू के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए लिया गया 1 करोड़ का लोन माफ कर दिया। इसके अलावा, उनके पड़ोसी जेक मालेते का 23.7 लाख का कर्ज भी माफ किया गया। हालांकि टाटा का ध्यान अधिकतर अपने कर्मचारियों और जरूरतमंदों पर था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को भी नजरअंदाज नहीं किया। उनके भाई जिमी टाटा को मुंबई के जुहू स्थित 16 करोड़ की संपत्ति मिली, जबकि उनकी सौतेली बहनों को उनकी कुल संपत्ति का एक-तिहाई हिस्सा दिया गया। बैंक में जमा 385 करोड़ की राशि भी परिवार के बीच बांटी गई। टाटा के करीबी दोस्त मेहली मिस्त्री को अलीबाग स्थित 6.2 करोड़ की संपत्ति और उनकी कुछ बंदूकें मिलीं। टाटा समूह में उनकी 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन (आरटीईएफ) को और 30 प्रतिशत हिस्सेदारी रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट (आरटीईटी) को दी गई। रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी सादगी और इंसानियत को प्राथमिकता दी, और उनकी वसीयत भी इसी का प्रमाण है। जहां उन्होंने दूसरों के लिए दिल खोलकर दान किया, वहीं अपने अंतिम संस्कार के लिए मात्र 2500 रखे। यह बताता है कि उनके लिए भौतिक संपत्ति से अधिक लोगों की भलाई मायने रखती थी।

अमेरिकी कोर्ट ने ...

अदालत ने पन्नू के दावे को गलत ठहराते हुए इसे खारिज कर दिया। पन्नू ने डोभाल और एक अन्य भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया है। संघीय अभियोजकों ने गुप्ता पर आरोप लगाया है कि उसने अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में भारत के एक सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर काम किया था। पन्नू ने अदालती दस्तावेजों में दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए 12-13 फरवरी को अमेरिका की यात्रा पर आए थे, तब डोभाल भी उनके साथ वाशिंगटन पहुंचे थे और इस दौरान उन्हें (डोभाल को) अदालती दस्तावेज सौंपने के लिए उसने *दो कानून पेशेवरों और एक जांचकर्ता* को नियुक्त किया था।

इमरान मसूद बोले- ये ...

अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो वे संपत्तियां अब वक्फ की नहीं रहेंगी। पंजीकरण कौन करेगा? आपके अधिकारी। जब यह 10 साल में नहीं किया जा सका तो 6 महीने में कैसे किया जाएगा? यह एक संविधान विरोधी विधेयक है। वहीं भाजपा की तरप से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक नहीं बल्कि उम्मीद (एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण, दक्षता और विकास) है। इस उम्मीद में सशक्तिकरण, दक्षता और विकास है। इसे देखते हुए देश की जनता इसका समर्थन कर रही है। कैथोलिक बिशप कांफ्रेंस ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ भारत, केरल काउंसिल ऑफ चर्चेज और केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल, ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे कई संगठनों ने इसका समर्थन किया है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि वक्फ में संशोधन का समय आ गया है क्योंकि यह अत्याचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसे खत्म करने और इसमें संशोधन करने का समय आ गया है। भारत को वक्फ के डर से मुक्ति चाहिए क्योंकि कांग्रेस के शासन में बने वक्फ कानून का मतलब था कि *खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही।*

दवा की कीमतों ...

और रैलियां करेगी। उन्होंने आम जनता से भी अपने-अपने स्तर पर इस मूल्यवृद्धि के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। 748 दवाओं की नई कीमतें मंगलवार से लागू हो चुकी हैं। एनपीपीए ने इनकी अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में 1.74 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इस सूची में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, बुखार और अन्य आवश्यक बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। यहां तक कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली पैरासिटामोल भी महंगी हो गई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश और राज्य के गरीब और मध्यमवर्गीय लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ दवाओं की कीमत 31.8 प्रतिशत तक बढ़ी है, जबकि कुछ की कीमतें 115.8 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने चिंता जताई कि जो लोग निजी अस्पतालों में महंगा इलाज नहीं करवा सकते, उनके लिए ये दवाएं जीवनरक्षक हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ शुक्रवार और शनिवार को राज्यभर में आंदोलन करेगी।

लालू की तबीयत ...

पर पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीपी बहुत ज्यादा डाउन होने की वजह से पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर उनके बेटे तेजस्वी यादव ने बड़ी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि शाम 7 बजे की फ्लाइट से लालू प्रसाद दिल्ली एम्स रवाना होंगे। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। वो जल्द ठीक हो जाएंगे। उनके कंधे पर जख्म था। जांच में लो बीपी की बात सामने आई। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ साल से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर अन्य स्वास्थ्य कारणों से उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया।साल 2022 में लालू को किडनी से जुड़ी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों की जांच में पता चला था कि सिर्फ 25 प्रतिशत किडनी ही काम कर रही है। इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी एक किडनी दान की। 5 दिसंबर 2022 को सिंगापुर में सफल ट्रांसप्लांट किया गया। लालू यादव को दिल की बीमारी भी है। 2021 में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में सजा काटने के दौरान उनकी हार्ट कंडीशन का पता चला। डॉक्टरों ने विशेषज्ञों से इलाज कराने की सलाह दी। इसके बाद सितंबर 2023 में मुंबई के एक अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई।

इसी महीने में होगा ...

नए अध्यक्ष को लेकर एकमत नहीं थे। भाजपा चाहती थी कि नेतृत्व ऐसा हो, जिसने नड्डा की तरह संगठन को सफलता दिलाई हो, जबकि आरएसएस की प्राथमिकता संगठन से जुड़े, विचारधारा से मजबूत और उसकी नीतियों को आत्मसात करने वाले नेता की थी। हालांकि, 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नागपुर में हुई मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि जल्द ही भाजपा को नया अध्यक्ष मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा इस महीने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक यह फैसला सार्वजनिक हो जाएगा।वहीं, 4 अप्रैल को संसद सत्र समाप्त होने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के भाजपा प्रदेश अध्यक्षों के नामों का एलान भी अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ एक औपचारिक नियुक्ति नहीं होती, बल्कि यह लोकसभा चुनाव 2029 और आने वाले राज्य चुनावों की रणनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

गौरव गोगोई ने सरकार ...

कहा कि कोई खंड-दर-खंड चर्चा नहीं हुई। इस पर गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष की तरफ से सुझाए गए एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि जिन्हें वक्फ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें जेपीसी में आमंत्रित किया गया। विधेयक के खिलाफ बहस करते हुए गौरव गोगोई ने चेतावनी दी कि सरकार भविष्य में अन्य अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आज वे एक समुदाय की जमीन को निशाना बना रहे हैं, कल वे दूसरे समुदाय को निशाना बनाएंगे। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संविधान पढ़ते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(1) में उल्लिखित *धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने* की किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वक्फ प्रबंधन से संबंधित है। इसका दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप से कोई लेना-देना नहीं है। किरेन रिजिजू के दावों का विरोध करते हुए गौरव गोगोई ने एक संशोधन की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को तभी वक्फ घोषित कर सकता है, जब वह कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करता हो। उन्होंने कहा कि क्या वे अन्य धर्मों से प्रमाण पत्र मांगेंगे कि आपने पांच साल पूरे किए हैं या नहीं? इस विधेयक में ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? सरकार धर्म के इस मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रही है। वक्फ (संशोधन) बिल, जिसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (यूएमईईडी) बिल भी कहा जाता है, का मकसद वक्फ संपत्तियों की बेहतरी और पारदर्शिता बढ़ाना है। इसमें डिजिटलीकरण, ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध कब्जों को हटाने जैसे सुधार प्रस्तावित हैं। बता दें कि 1995 में बना वक्फ अधिनियम लंबे समय से भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के कारण विवादों में रहा है।

जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने बरनाडी नदी के किनारे हलधा से बनिया सुपा तक नए तटबंध के निर्माण का उद्घाटन किया

गुवाहाटी। बाढ़ और कटाव से जुड़ी चुनौतियों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने आज बरनाडी नदी के किनारे हलधा से बनिया सुपा तक एक नए तटबंध के निर्माण का उद्घाटन किया। कामरूप ग्रामीण जल संसाधन प्रभाग के तत्वावधान में शुरू की गई इस परियोजना पर लगभग ?4.75 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। यह ध्यान देने योग्य है कि मंत्री ने क्षेत्रीय संपर्क और परिवहन में सुधार के उद्देश्य से कई सड़क विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। वर्ष 2025-26 के लिए नाबार्ड के आरआईडीएफ-एक्सएक्सएक्स1 के तहत एमएमपीपीएनए के तहत कार्यान्वित की गई इन पहलों में 1.00 किलोमीटर तक फैले बथन कलिता सुबुरी रोड का निर्माण शामिल है, जिसका अनुमानित बजट 71.50 लाख है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीडब्ल्यूसी रोड्स (एसओपीडी-जी) योजना के तहत कई सड़क निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। इनमें हलधा सहन मालीबाड़ी रोड, श्याम राय नामघर को डुमुनीचौकी एलपी स्कूल से जोड़ने वाली सड़क, करारा बथन रोड और मालीबाड़ी अर्जुनताल से हिंदुमोजली नदीपार रोड शामिल हैं। इन बुनियादी ढांचे के विकास की कुल अनुमानित लागत 64.09 लाख है। लोक निर्माण सड़क विभाग, उत्तरी कामरूप प्रादेशिक सड़क प्रभाग द्वारा संचालित इन अवसंरचना विकास परियोजनाओं से सड़क पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय निवासियों को लाभ होगा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। हलधा में आयोजित जनसभा में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने वर्तमान प्रशासन के दृष्टिकोण की तुलना पिछली सरकारों के दृष्टिकोण से की और कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों को उनके उचित लाभों से वंचित रखा और भर्ती और अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सरकारी पहलों पर प्रकाश डाला और कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इन पहलों में, उन्होंने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का उल्लेख किया, जिसके तहत लगभग 30 लाख महिला उद्यमियों को प्रत्येक को 10,000 की वित्तीय सहायता मिली है। इसके अलावा, उन्होंने निजुत मोइना योजना के माध्यम से शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जो लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से मेधावी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के राज्य के प्रयासों पर जोर दिया। मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के समर्थन का भी उल्लेख किया, विशेष रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के माध्यम से। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के साथ-साथ मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर असम अभियान पर भी प्रकाश डाला, जो उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है। क्षेत्र में बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए एक सुरक्षा दीवार के निर्माण के अनुरोध के जवाब में, मंत्री हजारिका ने पुष्टि की कि उचित उपाय किए जाएंगे। उन्होंने बाढ़ सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लगभग 500 मीटर तक फैली एक सुरक्षा दीवार के निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, मंत्री ने स्थानीय लोगों को एक एम्बुलेंस समर्पित की। यह प्रावधान राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के तहत संभव हुआ, जिसे विधायक दिगंत कलिता की पहल से सुगम बनाया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने कमालपुर के निवासियों से डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के लिए अपना समर्थन जारी रखने का आग्रह किया, और विकास की वर्तमान गति को बनाए रखने में निरंतर सार्वजनिक समर्थन के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में विधायक दिगंत कलिता, एएसटीसी के उपाध्यक्ष प्रणव ज्योति लाहकर, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता भास्कर ज्योति शर्मा, उत्तर कामरूप जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भास्कर ज्योति कलिता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

असम विस उपाध्यक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना

वक्फ संशोधन विधेयक की सराहना

गुवाहाटी (हिंस)। लोकसभा में बुधवार को पेश होने वाले वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमल मोमिन ने जोरदार समर्थन जताया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक *महान पहल* करार दिया, जो देश के वंचित मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए लाई गई है। मीडिया से बात करते हुए मोमिन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि पार्टी ने राजनीतिक फायदे के लिए गरीब मुस्लिम समुदाय का शोषण किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ने से रोका, जबकि पार्टी के अमीर नेता इसका फायदा उठाते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा गरीब मुस्लिमों का शोषण करने की नीति पर चली है। वे नहीं चाहते कि गरीब मुस्लिमों को बेहतर सुविधाएं और आजीविका मिले, जबकि पार्टी के धनी नेता इन गरीबों का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा, उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह इस विधेयक का समर्थन करे और अपनी पिछली गलतियों को सुधारे। मोमिन ने कहा कि मेरा कांग्रेस पार्टी को सुझाव है कि वे खुले मन से आगे आएं और इस विधेयक का समर्थन करें ताकि साबित हो सके कि वे वास्तव में गरीब मुस्लिम समुदाय के साथ हैं।

कामपुर स्टेशन पर चालू हुआ नया रोड ओवर ब्रिज

समपार फाटक संख्या एसटी- 35 यातायात के लिए बंद

गुवाहाटी (हिंस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) ने गुवाहाटी-लामडिंग सेक्शन के कामपुर स्टेशन पर समपार फाटक संख्या एसटी- 35 के स्थान पर एक महत्वपूर्ण रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) संख्या 114/ए का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया। सड़क यातायात में भीड़-भाड़ और गुवाहाटी-लामडिंग सेक्शन में हाल ही में पूर्ण हुई दोहरी लाइन से ट्रेनों के बढ़ते आवागमन के कारण समपार फाटक संख्या एसटी-35 के स्थान पर आरओबी के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। इस परियोजना को लगभग 64 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया गया। पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने आज बताया है कि नव निर्मित आरओबी का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने 30 मार्च को किया और अब यह सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, समपार फाटक संख्या एसटी-35, जिसका ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूनिट (टीयूवी) 6.70 लाख था, को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इससे एक महत्वपूर्ण रूकावट समाप्त होने के साथ-साथ क्षेत्र में ट्रेन परिचालन को बढ़ावा मिलेगा। आरओबी की कुल लंबाई 803 मीटर है, जिसमें 505 मीटर लंबा वायाडक्ट और 42 मीटर का बो स्टिंग गर्डर स्पैन शामिल है। 7.5 मीटर चौड़े मार्ग के साथ, यह वाहनों के सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करेगा। यह महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना स्थानीय यात्रियों के लिए निर्बाध रोड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे तेज तथा सुरक्षित यात्रा और अधिक बेहतर होगी। इसके अतिरिक्त, व्यस्त समपार फाटक के बंद होने से इस महत्वपूर्ण मार्ग पर रेल संरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, विलंबता में कमी आएगी और ट्रेन परिचालन की समग्र दक्षता में सुधार होगा। समपार फाटकों की समाप्ति ट्रेन परिचालन की संरक्षा को बढ़ाएगा और आरओबी पर सड़क परिवहन एवं राहगीरों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा। पूसीरे पूरे क्षेत्र में निर्बाध परिवहन, यात्री सुविधा और संरक्षा बढ़ाने के लिए बुनियादी संरचना के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। इस आरओबी के चालू होने से नगांव और कार्बी आंग्लांग जिलों के निवासियों को काफी लाभ होगा।

राभा हासोंग स्वायत्त शासित परिषद चुनाव के लिए मतदान शुरू

गुवाहाटी (हिंस)। असम में राभा हासोंग स्वायत्त शासित परिषद (आरएचएसी) चुनाव के लिए बुधवार को मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें दिखने लगीं। राज्य के 33 निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। चुनाव में कई राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं, तीन निर्वाचन क्षेत्रों में पहले ही तीन उम्मीदवार निर्विरोध विजयी घोषित हो चुके हैं, जिससे इन सीटों पर मतदान नहीं हो रहा है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, मतदान प्रक्रिया पूरे दिन चलेगी और शाम तक मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया तय समयानुसार शुरू होगी। स्थानीय प्रशासन ने मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। ज्ञात हो कि राभा हासोंग स्वायत्त शासित परिषद की कुल 40 सीटों में से चार सीटें मनोनित की जाती हैं। जबकि, 36 सीटों के लिए चुनाव होता है।

चलती बस में युवती से यौन उत्पीड़न के आरोप में दो गिरफ्तार, वाहन जब्त

श्रीभूमि (हिंस)। असम राज्य परिवहन निगम (एएसटीसी) द्वारा संचालित चलती यात्री बस में एक युवती का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बस को भी जब्त कर लिया गया है। श्रीभूमि के पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में पुष्टि की कि एएसटीसी के तहत संचालित एक निजी बस (एएस-24-6111) में बीती रात हुई दुर्भाग्यपूर्ण अपराध में शामिल तीन संदिग्धों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण और तकनीकी जांच के बाद दोनों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पंचग्राम निवासी जसीम उद्दीन लस्कर और सिलचर निवासी अबुल सलाम शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपियों में से एक बस चालक है और दूसरा बस यात्री है। इस बीच, तीसरा संदिग्ध अभी फरार है। हालांकि, पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का बयान भी लिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस सभी पहलुओं पर विचार करके घटना की गहराई से जांच करेगी। एक सवाल के जवाब में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यौन उत्पीड़न की शिकार युवती का श्रीभूमि सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी शारीरिक स्थिति स्थिर है। संभवतः सभी परीक्षण कराने के बाद उन्हें आज रात अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास ने भी कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षकों के परिजनों को एकमुश्त सहायता संभव : शिक्षामंत्री पेगू

गुवाहाटी (हिंस)। शिक्षामंत्री डॉ. रनोज पेगू ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार शिक्षा और शिक्षकों के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, काहिलीपारा में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षामंत्री डॉ. रनोज पेगू की उपस्थिति में कर्तव्य निर्वहन के दौरान मृत छह संविदा शिक्षकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की गई। इसी कार्यक्रम में सरकार द्वारा संचालित *आरोहण* योजना के तहत समग्र शिक्षा कामरूप महानगर के 116 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर शिक्षामंत्री ने दिवंगत शिक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और मेधावी छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह युग सूचना और प्रौद्योगिकी का है और छात्रों को तकनीकी सहायता से आगे बढ़ाने के लिए टैबलेट वितरण किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि असम सरकार मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत आज से राज्य के 11 जिलों के 200 विद्यालयों में मिसिंग भाषा में पढ़ाई शुरू कराई गई है। साथ ही, 106 स्कूलों में राभा और 28 स्कूलों में देउरी भाषा में शिक्षा की अनुमति दी गई है, जिससे राज्य में शिक्षा के माध्यमों की संख्या 9 से बढ़कर 14 हो गई है। इस कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा संचालक ममता होजाई और कामरूप महानगर जिले की स्कूल निरीक्षिका दीपिका चौधरी भी उपस्थित रहीं।

बीटीआर में एक नए राजनीतिक दल का गठन

बाक्सा (हिंस)। बोड़ोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) में एक नया राजनीतिक दल का गठन हुआ है। इस नए राजनीतिक दल का नाम *अल्टरनेटिव पार्टी ऑफ बोड़ोलैंड* रखा गया है। यह विशेष राजनीतिक दल पूर्व एनडीएफबी (नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोड़ोलैंड) के संरक्षण में स्थापित किया गया है। इस दल के अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक डॉ. अंजली दैमारी ने कहा कि यह दल मुख्य रूप से बोड़ो समुदाय के उस आक्रोश को दर्शाने के लिए बनाया गया है, जो शांति समझौते के सही ढंग से लागू न होने के कारण उत्पन्न हुआ है। आज गठित नए राजनीतिक दल ने घोषणा की है कि वह आगामी बोड़ोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) चुनावों में भी हिस्सा लेगा। अंजली दैमारी ने वर्तमान बीटीसी परिषद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बोड़ो समुदाय को न्याय और सुरक्षा देने में असफल रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि जेलों में बंद एनडीएफबी के नेताओं की रिहाई का मुद्दा अब सरकार के लिए गौण विषय बन गया है। आज मुसलपुर के बड़बड़ी स्थित एनडीएफबी शिविर में आयोजित एक सभा में इस राजनीतिक दल ने अपनी कार्यकारिणी समिति का गठन किया। इसमें डॉ. अंजली दैमारी को अध्यक्ष, प्रदीप कुमार ब्रह्म को प्रशासनिक सचिव और जगदीश बसुमतारी को सांगठनिक सचिव बनाया गया है। इस समिति में कुल 21 सदस्य शामिल किए गए हैं।

राज्यपाल ने माधवदेव विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपाधियां प्रदान कीं

डिग्री धारकों से सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को सशक्त बनाने का किया आह्वान

लखीमपुर (हिंस)। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कहा है कि नारायणपुर की पावन भूमि पर स्थापित और असम की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित माधवदेव विश्वविद्यालय केवल ज्ञान के प्रसार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों में नैतिकता, सेवा की भावना और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। नारायणपुर में बुधवार को माधवदेव विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में स्नातकों को संबोधित करते हुए आचार्य ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। इसे ध्यान में रखते हुए, माधवदेव विश्वविद्यालय ने भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया है। राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए इस अवसर पर माधवदेव और उनके पूज्य गुरु श्रीमंत शंकरदेव के प्रति गहरा सम्मान और श्रद्धा व्यक्त की। आचार्य ने योग, एनएसएस, एनसीसी, रोवर और रेंजर को मूल्य आधारित अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की विश्वविद्यालय की नीति की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से समृद्ध करेगी, बल्कि उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत करेगी। राज्यपाल ने स्नातकों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होता है। यह केवल आपकी शिक्षा के औपचारिक समापन का प्रतीक नहीं है, बल्कि आपके ज्ञान और कौशल की वास्तविक परीक्षा की शुरुआत भी है। आपकी शिक्षा का वास्तविक मूल्य आपके परीक्षा अंकों से नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए आपके योगदान से आंका जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जब आप इस विश्वविद्यालय से बाहर निकलें, तो याद रखें कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं है; यह समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी का आधार भी है। आप इस विश्वविद्यालय की परंपराओं, आदर्शों और शिक्षाओं के वाहक हैं। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का लोगों में निवेश करने का विजन तीन स्तंभों- शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य पर आधारित है। उन्होंने कहा कि उनके विजन के अनुरूप सरकार ने शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाने के लिए पुरानी व्यवस्था में सुधार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की है। राज्यपाल ने कहा कि एनईपी 2020 भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा पर आधारित एक मजबूत शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करती है और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है तथा भारत को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करती है। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों से माधवदेव विश्वविद्यालय में प्राप्त ज्ञान, कौशल और अनुभव का सर्वोत्तम उपयोग करने और विभिन्न सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने का आह्वान किया। आचार्य ने कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ज्ञान के प्रसार, कौशल संवर्धन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं, जो मिलकर राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान करते हैं। राज्यपाल ने माधवदेव विश्वविद्यालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि कम समय में ही विश्वविद्यालय ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अपनी एक मजबूत पहचान स्थापित कर ली है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय 15 स्नातक कार्यक्रम, 13 स्नातकोत्तर कार्यक्रम और 11 विभागों में पीएचडी कार्यक्रम संचालित करता है, जिसमें कुल 2,760 छात्र नामांकित हैं। माधवदेव विश्वविद्यालय की एक अनूठी विशेषता बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि सभी स्नातक छात्रों के लिए अनिवार्य विषय के रूप में *माधवदेव* का अध्ययन करना एक सराहनीय पहल है, जो छात्रों को असम के महान वैष्णव संत की शिक्षाओं से परिचित होने में मदद करती है, जिससे उनमें नैतिकता और मानवता के प्रति जागरूकता बढ़ती है।

लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद महिला प्रकोष्ठ की शुरुआत

गुवाहाटी (विभास)। लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद पूर्वोत्तर की महिला प्रकोष्ठ ने गणगौर विसर्जन मेले में आए हुए श्रद्धालुओं के बीच आइसक्रीम वितरण कार्य करके महिला प्रकोष्ठ की विधिवत शुरुआत कर दी। इस अवसर पर नगर निगम के पार्षद सौरभ झुनझुनवाला ने महिला प्रकोष्ठ के स्टॉल का उद्घाटन करते हुए कहा कि महिलाओं को संगठित होकर जन सेवा कार्य करना यह हमारे मारवाड़ी समाज की एक विशिष्टता है। लक्ष्मणगढ़ की प्रवासी महिलाओं ने भी गुवाहाटी में अपना एक प्रकोष्ठ प्रारंभ कर अपना प्रथम कार्यक्रम गणगौर विसर्जन मेले में प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि गणगौर विसर्जन उत्सव के दौरान ही लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद के

सलाहकार जयप्रकाश गोयंका, राजकुमार शर्मा सोती, लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद के अध्यक्ष विशाल भातरा, सचिव प्रियम जालान, राकेश भातरा, विवेक शर्मा भातरा, संपत मिश्र की उपस्थिति में प्रकोष्ठ का गठन कर मीनाक्षी मिमानी को संयोजिका और रूबी जालान को सह संयोजिका नियुक्त किया। स्लॉट में श्रद्धालुओं को आइसक्रीम वितरण कार्यक्रम की संयोजिका रितु भातरा के अलावा वंदना शर्मा, स्वाती भातरा एवं अन्य सदस्योंओ ने उपस्थित होकर अपना सहयोग दिया।

चिरांग में स्वास्थ्य एवं कल्याण शिविर ने निःशुल्क चिकित्सा सेवा एवं जागरूकता प्रदान की

बिजनी। स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ असम के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला स्वास्थ्य सोसायटी, चिरांग ने 69 नंबर उत्तर काजलगांव एलपी स्कूल, काजलगांव में स्वास्थ्य एवं कल्याण शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन चिरांग जिला आयुक्त जतिन बोरा ने किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों एवं समुदाय के सदस्यों को एक दिन के लिए एक साथ लाया गया, जो स्वास्थ्य, जागरूकता एवं सुलभ चिकित्सा सेवा के लिए समर्पित था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की इस पहल का उद्देश्य स्त्री रोग, नेत्र रोग, मनोरोग, ईएनटी, बाल रोग, त्वचा रोग एवं सामान्य चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं, जिससे सुलभ स्वास्थ्य सेवा सहायता सुनिश्चित हुई। शिविर में उन व्यक्तियों के लिए

एबीएचए (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) नंबर बनाने की सुविधा भी प्रदान की गई, जिनके पास ये नहीं थे, ताकि उन्हें डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत किया जा सके। चिकित्सा परामर्श के अलावा, शिविर में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं पर कार्यशालाएं, योग सत्र और ग्राम परिषद विकास समिति (वीसीडीसी) के निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी वीडियो की स्क्रीनिंग भी शामिल थी। प्रतिभागियों को शामिल करने और संवादात्मक तरीके से स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्विज, स्वास्थ्य लॉटरी और योग प्रदर्शन सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। शिविर में स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक डॉ. रेजाउल करीम, एसडीएम और एचओ डॉ. उत्तम विश्वास, जिला निगरानी अधिकारी डॉ. द्विगेंद्र रामचियारी, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. राजेश पांडे और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) और ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू) के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जिला और उप-मंडल स्वास्थ्य अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, एएनएम, मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) सेवाओं और स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिससे यह बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक सहयोगात्मक प्रयास बन गया।

संपादकीय

स्मार्ट सिटी कितनी हकीकत

देश ने करीब दस साल पहले सौ स्मार्ट सिटी के कदम चुने, तो वकालत के चश्मों ने सर्वप्रथम धर्मशाला देखा, फिर शिमला को निहारा और इस तरह हिमाचल में शहरीकरण को एक नए पहलू में अंगीकार किया गया। यह दीगर है कि इस फैसले में फासले बहुत रहे हैं और यही वजह है कि तीसरी मोहलत मार्च आते-आते गुजर गई और अब फिर अर्जियां खाली तख्तियों पर गुजारिश कर रही हैं। न धर्मशाला की परियोजनाएं और न ही शिमला की महत्त्वाकांक्षा में स्मार्ट सिटी अपनी जवानी में आई। एक मुकाबला इन दोनों शहरों के बीच व्यवस्था का भी रहा और खींचतान से समय की बर्बादी कर दी। प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी घोषित होते ही धर्मशाला को नाको चने चबाने के लिए भाजपा के सुरेश भारद्वाज अदालत सिर्फ इसलिए चल गए कि यह चयन शिमला की छाती पर मूंग दल रहा था। यही सुरेश भारद्वाज जब शहरी विकास मंत्री बनते हैं, तो शिमला स्मार्ट सिटी की पलकें खोलने के बजाय धर्मशाला के कई रोशनदान बंद करने लगे और इस अखाड़े में परियोजनाएं सिकुड़ गईं, राज्य सरकार की हिस्सेदारी बदल गई। अगर डबल इंजन सरकार की नीयत से भाजपा की तत्कालीन सरकार पैरवी करती तो अंग्रेजों के बसाए दो शहर हिमाचल के शहरी विकास को आगे के लिए एक मॉडल की हैसियत और शहरी आर्थिकी को प्रमाणित करते।

अब अर्ज किया है कि स्थिति में हिमाचल के दो स्मार्ट शहर अपनी हस्ती का सामान लेकर आए हैं। देश ने करीब दस साल पहले सौ स्मार्ट सिटी के कदम चुने, तो वकालत के चश्मों ने सर्वप्रथम धर्मशाला देखा, फिर शिमला को निहारा और इस तरह हिमाचल में शहरीकरण को एक नए पहलू में अंगीकार किया गया। यह दीगर है कि इस फैसले में फासले बहुत रहे हैं और यही वजह है कि तीसरी मोहलत मार्च आते-आते गुजर गई और अब फिर अर्जियां खाली तख्तियों पर गुजारिश कर रही हैं। न धर्मशाला की परियोजनाएं और न ही शिमला की महत्त्वाकांक्षा में स्मार्ट सिटी अपनी जवानी में आई। एक मुकाबला इन दोनों शहरों के बीच व्यवस्था का भी रहा और खींचतान से समय की बर्बादी कर दी। प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी घोषित होते ही धर्मशाला को नाको चने चबाने के लिए भाजपा के सुरेश भारद्वाज अदालत सिर्फ इसलिए चल गए कि यह चयन शिमला की छाती पर मूंग दल रहा था। यही सुरेश भारद्वाज जब शहरी विकास मंत्री बनते हैं, तो शिमला स्मार्ट सिटी की पलकें खोलने के बजाय धर्मशाला के कई रोशनदान बंद करने लगे और इस अखाड़े में परियोजनाएं सिकुड़ गईं, राज्य सरकार की हिस्सेदारी बदल गई। अगर डबल इंजन सरकार की नीयत से भाजपा की तत्कालीन सरकार पैरवी करती तो अंग्रेजों के बसाए दो शहर हिमाचल के शहरी विकास को आगे के लिए एक मॉडल की हैसियत और शहरी आर्थिकी को प्रमाणित करते। भले ही सुरेश भारद्वाज धर्मशाला के इंटेग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एरिया को दरी समझकर शिमला में बिछाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इससे स्मार्ट सिटी का आधारभूत प्रारूप ही चोटिल हो गया। ऐसा नहीं इस दौरान सरवीण चौधरी भी कुछ समय शहरी विकास मंत्री रहीं, लेकिन वह धर्मशाला के तत्कालीन विधायक स्व. किशन कपूर के साथ व्यक्तिगत विवादों के कारण स्मार्ट सिटी परियोजना के महत्त्व को समझ ही नहीं पाईं। आज जब पुनः दो स्मार्ट सिटी परियोजनाएं मुकम्मल होने की दरख्वास्त दे रही हैं, तो इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी समझना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर अन्य 84 स्मार्ट शहरों में करीब पंद्रह हजार करोड़ के कार्य अधूरे हैं। हिमाचल में शिमला के बजाय धर्मशाला में कुछ हद तक परियोजनाओं के अर्थ दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों ही शहरों में स्मार्ट सिटी के धन से सरकारों ने अपने विभागीय खर्च के वैकल्पिक मार्ग चुने हैं। मसलन शिमला में बीस तो धर्मशाला में 15 इलेक्ट्रिक बसों पर करोड़ों खर्च करके इन्हें बिना शर्त-बिना फर्ज अदा किए एचआरटीसी को सौंप दिया। क्या इससे शहरी या स्थानीय परिवहन सेवाओं में सुधार हुआ। धर्मशाला में अगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक बहुआयामी बस स्टैंड विकसित होता, तो आय का संचार भी होता, लेकिन इसके बजाय एचआरटीसी की वर्कशाप में बारह करोड़ लगा दिए गए। स्मार्ट सिटी जोनल अस्पताल को मशीनें, स्कूलों के स्मार्ट रूम और उधर शिमला में एंट्री गेट, बुक कैफे और लोहे व कंक्रीट के जाल बुन रही थीं। शिमला में दो बस अड्डों व लिफ्टों का निर्माण, धर्मशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबाल ग्राउंड व फूड स्ट्रीट जैसी परियोजनाएं सार्थक हो सकती हैं, लेकिन अभी भी रेहड़ी-फड़ी वाले फुटपाथों पर घमासान मचाए हुए हैं, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था शहरी जीवन को अफरातफरी में फंसाए हुए हैं। बस स्टाप सिर्फ बनाए गए, सुविधा के लिए चलाए नहीं गए। कहना न होगा स्मार्ट सिटी के विजन को हिमाचल का शहरीकरण न कुछ सीख और न ही कुछ कर पाया। यह दीगर है कि अब शिमला-धर्मशाला में नगर निगमों के बाद होड़ यह है कि इनकी संख्या पटवारखानों की तरह बढ़ जाए, लेकिन परिकल्पना, बजट और आर्थिक स्रोत क्या होंगे, कोई नहीं जानता। कौनसा शहर किस रूप-किस प्रारूप में बेहतर नागरिक सुविधाओं और आर्थिक क्षमता में निखर सकता है, कोई कल्पना नहीं। बहुत पहले स्व. सुखराम ने मंडी शहर के केंद्रीय हिस्से की व्यथा को इंदिरा मार्किट की क्षमता में बदल दिया था।

भारत में यदि गरीबी को जड़ मूल से नष्ट करना है तो कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लागू करना ही होगा

कृषि क्षेत्र में करवट बदलता भारत

प्रह्लाद सबनानी

भारत ने हालांकि आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त सफलताएं अर्जित की हैं और भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तथा शीघ्र ही अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही, भारत आज विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बन गया है। परंतु, इसके आगे की राह अब कठिन है, क्योंकि केवल सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र के बल पर और अधिक तेज गति से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना होगा। भारत में हालांकि कृषि क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं और भारत आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। परंतु, अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

भारत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जबकि, कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 18 प्रतिशत के आस पास बना हुआ है। इस प्रकार, भारत में यदि गरीबी को जड़ मूल से नष्ट करना है तो कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लागू करना ही होगा। भारत ने हालांकि आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त सफलताएं अर्जित की हैं और भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तथा शीघ्र ही अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही, भारत आज विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बन गया है। परंतु, इसके आगे की राह अब कठिन है, क्योंकि केवल सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र के बल पर और अधिक तेज गति से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना होगा। भारत में हालांकि कृषि क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं और भारत आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। परंतु, अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। किसानों के पास पूंजी का अभाव रहता था और वे बहुत ऊंची ब्याज दरों पर महाजनों से ऋण लेते थे और उनके जाल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे, परंतु, आज इस समस्या को बहुत बड़ी हद्द तक हल किया जा सका है और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को आसान नियमों के अंतर्गत बैकों से पर्याप्त ऋण की सुविधा उपलब्ध है और इस सुविधा का लाभ आज देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं। दूसरे, इसी संदर्भ में किसान सम्मान निधि योजना भी किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है और इस योजना का लाभ भी करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इससे किसानों की कृषि सम्बंधी बुनियादी समस्याओं को दूर करने के सफलता मिली है। भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। देश के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। इस समस्या को हल करने के उद्देश्य से भारत सरकार प्रति बूंद अधिक फसल की रणनीति पर काम कर रही है एवं सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है ताकि कृषि के क्षेत्र में पानी के उपयोग को कम किया जा सके तथा जल संरक्षण के साथ सिंचाई की लागत भी कम हो

सके। देश में कृषि जोत हेतु पर्याप्त भूमि का अभाव है और देश में सीमांत एवं छोटे किसानों की संख्या करोड़ों की संख्या में हो गई है। जिससे यह किसान किसी तरह अपना और परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं इनके लिए कृषि लाभ का माध्यम नहीं रह गया है। इन तरह की समस्याओं के हल हेतु अब केंद्र सरकार विभिन्न उत्पादों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में, मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखकर, वृद्धि करती रहती है, इससे किसानों को अत्यधिक लाभ हो रहा है। भंडारण सुविधाओं (गोदामों एवं कोल्ड स्टोरेज का निर्माण) में पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई है एवं साथ ही परिवहन सुविधाओं में सुधार के चलते किसान कृषि उत्पादों को लाभ की दर पर बेचने में सफल हो रहे है अन्यथा इन सुविधाओं में कमी के चलते किसान अपने कृषि उत्पादों को बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर हुआ करता था। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना भारी मात्रा में की जा रही है इससे कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल रहा है एवं कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने में सफलता मिल रही है। आज भारत में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि उर्वरकों के उपयोग की आवश्यकता कम हो एवं कृषि उत्पादकता बढ़े। इस संदर्भ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी किसानों की मदद कर रही है इससे किसान कृषि भूमि पर मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कृषि उत्पाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार को स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसान सीधे ही उपभोक्ता को उचित दामों पर अपनी फसल को बेच सके। साथ ही, कृषि फसल बीमा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश में सूखे, अधिक वर्षा, चक्रवात, अतिवृष्टि, अग्नि आदि जैसी प्रकृतिक आपदाओं के चलते प्रभावित हुई फसल के नुक्सान से किसानों को बचाया जा सके। आज करोड़ों की संख्या में किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं। देश में खेती किसानी का काम पूरे वर्ष भर तो रहता नहीं है अतः किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन निर्मित करने के उद्देश्य से डेयरी, पशुपालन, मधु मक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन आदि कृषि सहायक क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को अतिरिक्त आय की सुविधा मिल सके। विश्व के विभिन्न देशों ने अपनी आर्थिक प्रगति के प्रारम्भिक चरण में कृषि क्षेत्र का ही सहारा लिया है। औद्योगिक क्रांति तो बहुत बाद में आती है इसके पूर्व कृषि क्षेत्र को विकसित अवस्था में पहुंचाना होता है। भारत में भी आज कृषि क्षेत्र, देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, जो न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि करोड़ों नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर भी निर्मित करता है। साथ ही, औद्योगिक इकाईयों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र की महत्ता आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार बनी रहेगी क्योंकि इस क्षेत्र से पूरी दुनिया के नागरिकों के लिए भोजन, उद्योग के लिए कच्चा माल एवं रोजगार के अवसर कृषि क्षेत्र से ही निकलते रहेंगे। हां, कृषि क्षेत्र में आज हो रही प्रौद्योगिकी में प्रगति के चलते किसानों को कम भूमि पर, मशीनों का उपयोग करते हुए, कम पानी की आवश्यकता के साथ भी अधिक उत्पादन करना सम्भव हो रहा है। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ कृषि उत्पाद की लागत कम हो रही है और किसानों के लिए खेती एक उद्योग के रूप में पनपता हुआ दिखाई दे रहा है और अब यह लाभ का व्यवसाय बनता हुआ दिखाई देने लगा है। केला, आम, अमरूद, पपीता, नींबू जैसे कई ताजे फलों एवं चना, भिंडी जैसी सब्जियों, मिर्च, अदरक जैसे प्रमुख मसालों, जूट जैसी रेशेदार फसलों, बाजरा एवं अरंडी के बीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों एवं दूध के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है। दुनिया के प्रमुख खाद्य पदार्थों यथा गेहूं एवं चावल का भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत वर्तमान में कई सूखे मेवे, कृषि आधारित कपड़े, कच्चे माल, जड़ और कांड फसलों, दालों, मछली पालन, अंडे, नारियल, गन्ना एवं कई सब्जियों का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है।

दृष्टि कोण

हिमालयी प्राकृतिक स्वरूप का संरक्षण जरूरी

गत माह उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन हुआ। चमोली जनपद के सीमांत गांव माणा के समीप हुए हिमस्खलन के बाद उसके नीचे 55 श्रमिक दब गए थे। इनमें से 50 श्रमिकों को तो कुछ घंटों के बाद सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन 4 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। जिस दिन सीमा सडक़ संगठन के श्रमिक हिम से ढके मार्गों को साफ कर रहे थे, उससे एक-दो पहले लगभग पूरी हिमालय श्रृंखला में तेज वर्षा के साथ अत्यधिक हिमपात भी हुआ था। चमोली में भी बहुत अधिक हिमपात हुआ। यह पहली बार नहीं है, जब उत्तराखंड के संवेदनशील पर्वतीय जनपद में इस तरह की दुर्घटना हुई है। उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में भी गत कई वर्षों से ऋतुविकृतियों के कारण अनेक दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। प्रायः वर्षा ऋतु में तो पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक विप्लवों, विघटनों, विचलनों एवं विनाशक गतिविधियों का सामना करते ही करते हैं, लेकिन इस बार तो बसंत ऋतु में भी हिमालयी पट्टिका में वर्षा व हिमपात के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित व असुरक्षित हुआ है। अभी भी स्थिति संतुलित नहीं है। प्रति वर्ष, प्रति माह, प्रति सप्ताह, प्रति दिन और एक दिन में भी प्रहर-प्रति-प्रहर पर्यावरण की गति भयंकर असंतुलन को प्राप्त हो रही है। दस-बारह वर्ष पूर्व केदारनाथ में हुई अतिवृष्टि के बाद तो उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग अत्यंत संवेदनशील एवं शक्तिहीन हो चुके हैं। तब से कई प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वर्षाजन्य, हिमजन्य और भूकंपजन्य आपदाओं की निरंतरता के कारण पर्वतों का भौगोलिक स्थायित्व समाप्त हो चुका है। वर्षा ऋतु में तो पहाड़ों पर अतिवृष्टियों की आशंकाएं प्रतिक्षण बनी रहती हैं। इस बार तो बसंत ऋतु में भी मौसम का विचलन प्राकृतिक विपदा के रूप में सम्मुख है। यह विचित्र है। हमें प्रकृति के इस संकेत पर ध्यान देना चाहिए। हिमालय के पर्वतों का, विकास-यात्रा तीव्र करने के लिए जिस प्रकार दोहन किया जा रहा है, उस पर नियंत्रण एवं प्रतिबंध लगाने की युक्तियां करनी होंगी। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध सामरिक दीवाल के रूप में उपयोग होती आ रही हिमालयी पट्टी को धीरे-धीरे इसके स्वाभाविक स्वरूप में छोड़ देने का समय आ चुका है। जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल और फिर उत्तराखंड तक बांधों, विद्युत उत्पादन निर्माणियों व राजमार्गों के निर्माण के लिए पर्वतीय संरचनाओं को जिस प्रकार व्यापक स्तर पर तोड़ा-फोड़ा-जोड़ा गया और जिस तरह आए दिन इनकी टूट-फूट हो रही है, उससे प्रतिकूल प्राकृतिक स्थितियां उत्पन्न होती जा रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि शत्रु देशों के विरुद्ध इन्हें सामरिक संसाधन बनाने हेतु किए जा रहे तरह-तरह के निर्माण कार्य आगामी दिनों में बड़े प्राकृतिक विप्लव का कारण बनें। आज विद्युतीय आवश्यकताओं के लिए पहाड़ों पर बांध निर्माण से लेकर परिवहन के लिए मार्ग निर्माण के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। आधुनिक व आर्थिक विकास की प्रतिस्पद्र्धा, चकाचौंध में ऐसे निर्माण कार्यों के विनाशक परिणामों की जानबूझ कर उपेक्षा की जा रही है। जम्मू-कश्मीर से नीचे हिमाचल और फिर उत्तराखंड में उतरती हुई हिमालय पर्वतों की श्रृंखलाएं भीतर ही भीतर चट्टानों से रिक्त होती जा रही हैं। पर्वतों के बहुत नीचे कहीं गहराई में एक-दूसरे पर अवलंबित रहीं चट्टानें अपने स्थान से खिसक चुकी हैं। आधुनिक यंत्रों, विस्फोटकों और खुदाई की मशीनों द्वारा जितनी तेजी से पहाड़ काटे जा रहे हैं तथा जितनी गहराई तक उनकी खुदाई की जा रही है, उतनी ही तेजी व गहराई से धरातल पर हिमालयी पर्वतों की पकड़ शक्तिहीन हो रही है। संतुलित भूस्थापन में पर्वतों की बड़ी भूमिका होती है। पर्वतों पर निर्माण कार्यों की तेजी से संपूर्ण पर्वतीय पारिस्थितिकी ही असंतुलित नहीं हो रही, अपितु धरती का पूरा ऋतुचक्र भी विकृत हो रहा है। फलस्वरूप पूरे भारत और विश्वभर में अतिवृष्टि, भूकंपन, हिमस्खलन, शीताधिकता, ग्रीष्माधिकता की ऋतुविकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। समशीतोष्ण पारिस्थितिकी में कमी और महामारियों की प्राकृतिक परिस्थितियों में वृद्धि हो रही है। भला मनुष्य के लिए ऐसे आधुनिक, भौतिक और प्रगतिपरक विकास के क्या मायने होंगे, जो उसके सशरीर होने के मुख्य आधार पंचतत्त्वों को ही दिन-प्रतिदिन लील रहा हो। इस पर गंभीर होकर सोचना होगा। इस पर बार-बार और निरंतर विचार-विमर्श करना होगा। यदि संपूर्ण पृथ्वी के ऋतु असंतुलन पर विचार करते हुए इस दिशा में चिंतन किया जाए, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अखिल भारत व भारतीय महाद्वीप की मौसम संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए हिमालय पर्वत और इससे संबद्ध पूरी पर्वतमाला को प्राकृतिक रूप-स्वरूप में संरक्षित रखना अति अनिवार्य है। हिमालयी शैल-श्रृंखला को विद्युत उत्पादन, पर्यटन वद्र्धन और सडक़ मार्ग निर्माण के माध्यम से विकास की अंधभेंट चढ़ाना पर्यावरणीय व मानवीय दृष्टि से अत्यंत हानिकारक होगा।

कुछ अलग

जल-थल में प्लास्टिक

तमाम नये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय शोध-सर्वेक्षण चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी सांसों, पेयजल व फसलों में घातक माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी है। विश्व की कई शोध पत्रिकाओं में छपे शोध-लेख समय-समय पर विभिन्न अध्ययनों के चेताने वाले निष्कर्ष प्रकाशित करते रहते हैं। यह बात अलग है कि कई निष्कर्षों को लेकर विदेशी बाजार व कारोबारियों के लक्ष्य भी होते हैं। चिंता की बात यह भी है कि विकासशील देशों में सरकारें रोटी, कपड़ा व मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं के जुगाड़ में लगे रहने और गरीबी की समस्या से जूझते हुए, स्वास्थ्य के उन उच्च गुणवत्ता मानकों को वरीयता नहीं दे पाती, जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप हों। ऐसा ही एक अध्ययन जर्मन ब्रिटिश अकादमिक कंपनी स्प्रिंग नेचर द्वारा एक पर्यावरण विषयक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने केरल में दस प्रमुख ब्रांडों के बोतलबंद पानी को अध्ययन का विषय बनाया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि प्लास्टिक की बोतल के पानी का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रतिवर्ष 153 प्लास्टिक कण प्रवेश कर जाते हैं। निश्चय ही यह चिंता का विषय है। हालांकि, सर्वेक्षण के लिये केरल को ही चुनना और बोतलबंद पानी बेचने वाली भारतीय कंपनियों को चुनने को लेकर कई सवाल पैदा हो सकते हैं। दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बोतलबंद पानी बेचने का बड़ा प्रतिस्पर्धी कारोबार है। आम आदमी के मन में सवाल उठ सकते हैं कि कहीं भारतीय बोतलबंद पेय बाजार को तो निशाने पर नहीं लिया जा रहा है। दुनिया के बड़े कारोबारी देश भारत के बड़े उपभोक्ता बाजार पर ललचाई दृष्टि रखते हैं। इसके बावजूद मुद्दा गंभीर है और हमारी सरकारों को अपने स्तर पर गंभीर जांच-पड़ताल करनी चाहिए। इस दिशा में न केवल केरल बल्कि अन्य राज्यों में भी ऐसे ही अध्ययन होने चाहिए। वैसे तो एक खास वर्ग ही बोतलबंद पानी का उपयोग करता है, लेकिन पानी के अन्य स्रोतों का भी गंभीर अध्ययन किया जाना चाहिये। इसमें सरकारी जल आपूर्ति को भी शामिल करना जरूरी है। हमारे जीवन में जहर घोल रहे माइक्रोप्लास्टिक के हवा व पेड़-पौधों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर भी कई अध्ययन सामने आए हैं। पिछले दिनों एक अध्ययन में मनुष्य के मस्तिष्क में प्लास्टिक के नैनो कणों के पहुंचने पर चिंता जतायी गई थी। दावा था कि प्रतिदिन सैकड़ों माइक्रोप्लास्टिक कण सांसों के जरिये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सर्वविदित है कि देश के नीति-नियंताओं की कार्यस्थली दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। कमोबेश देश के कई अन्य शहर भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। प्रदूषण के कारण प्लास्टिक कण हमारी जीवन प्रत्याशा को घटा रहे हैं और कैंसर जैसे कई घातक रोग साथ में दे रहे हैं। विडंबना देखिये न तो सरकारें इस गंभीर संकट के प्रति सचेत हैं और न ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जनता जागरूक है। वहीं मुफ्त की रेवड़ियों की आस रखने वाले मतदाता इस गंभीर संकट को चुनावी मुद्दा बनाने की बात कभी नहीं करते। संकट तो यहां तक बढ़ गया है कि प्लास्टिक के कण पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने लगे हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला में शामिल कई खाद्यान्नों की उत्पादकता में गिरावट आ रही है। ऐसा निष्कर्ष अमेरिका-जर्मनी समेत कई देशों के साझे अध्ययन के बाद सामने आया है। दरअसल, प्लास्टिक कणों के हस्तक्षेप के चलते पौधों के भोजन सृजन की प्रक्रिया बाधित हो रही है।

देश दुनीया से

नेपाली राजशाही के लिए हिंसक प्रतिरोध के निहितार्थ

इसके बाद नेपाली राजशाही के 240 साल के इतिहास में सबसे बड़ा रहस्यमय और दुर्भाग्यपूर्ण पल सामने आया। वर्ष 2001 में बीरेंद्र के परिवार को भारी सुरक्षा वाले शाही महल में गोली मार दी गई। इसके बाद शुरू शाही जांच में तत्कालीन युवराज दीपेंद्र को नरसंहार के लिए दोषी ठहराया गया, जबकि वे कुछ दिनों तक बेहोश रहे, उन्हें कोमा में राजा घोषित किया गया, और उनकी मृत्यु हो गई। यह जांच बीरेंद्र के दो भाइयों में से पहले, ज्ञानेंद्र की निगरानी में हुई। ज्ञानेंद्र की नीयत पर सवाल भी उठाये गए। फिर जांच की लीपापोती हो गई। ज्ञानेंद्र और उनके पुत्र प्रिंस पारस की सार्वजनिक छवि उतनी अच्छी नहीं थी। लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि युवराज दीपेंद्र ने अकेले ही अपने पिता, माता, भाई, बहन और दादी को गोली मार दी होगी। दरबार हत्याकांड विदेशी षड्यंत्र भी साबित नहीं हो पाया। ज्ञानेंद्र 1950 के दशक में पहली बार चार साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठे थे। तब ज्ञानेंद्र के दादा, राजा त्रिभुवन ने राणाओं के खिलाफ विद्रोह किया था, और दिल्ली निर्वासित हो गए थे। हालात ने उन्हीं ज्ञानेंद्र को 4 जून, 2001 को दोबारा से ताज पहनने का अवसर दिया। ज्ञानेंद्र ने पांच साल के कालखंड में लोकतांत्रिक ताकतों को अलग-थलग कर दिया। अंततः सत्ता में आये माओवादियों ने 28 मई, 2008 को नेपाल की संविधान सभा के जरिये राजशाही समाप्त कर दी। लेकिन, पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र और उनके परिवार को आवास, सुरक्षा सुविधाएं शासन द्वारा दिया जाना जारी रहा। नेपाल में जब तक राजाशाही थी, नरेश भगवान विष्णु के अवतार और हिन्दू राष्ट्र के संरक्षक माने जाते थे। विगत कुछ वर्षों से राजशाही समर्थक हिंदू राष्ट्र की वापसी के एजेंडे को सुलगाने लगे थे। 11 मार्च,

2025 को खबर आई कि नेपाल में इस एजेंडे के समर्थकों ने राजा ज्ञानेंद्र के साथ उ.प्र. के मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर भी लहराते हुए नारे लगाए। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र उससे पहले, 30 जनवरी, 2025 को गोरखपुर अपने इष्ट देव, गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आये थे, तब उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। गत 1 अप्रैल, 2014 को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता अशोक सिंघल ने कहा था, कि अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। फिर चौतारा में एक मंच योगी आदित्यनाथ के साथ साझा करते हुए, अशोक सिंघल ने वही बात दोहराई कि हिन्दू राष्ट्र और राजतंत्र की वापसी होगी। 17 नवंबर, 2015 को 89 वर्ष के अशोक सिंघल, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में सिधार गए, नेपाल को हिन्दू राष्ट्र दोबारा से बनाने का सपना अधूरा रह गया। इस बीच, परदे के पीछे से ज्ञानेंद्र के लोग दिल्ली दरबार से संपर्क साधते रहे. अपरोक्ष रूप से ज्ञानेंद्र ने अपने दो निकटस्थ ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉ. कर्ण सिंह से भी राजशाही वापसी में मदद की उम्मीद तोड़ी नहीं थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां, माधवी राजे (किरण राज्य लक्ष्मी देवी), नेपाल के शाही परिवार से थीं। और डॉ. कर्ण सिंह की पत्नी महारानी यशो राज्य लक्ष्मी नेपाल के अंतिम राणा प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर परिवार से। दोनों अब दिवंगत हैं, लेकिन नेपाल के शाही परिवारों से भारतीय रजवाड़ों का भावनात्मक रिश्ता बरक़रार है। यह कहना कठिन है, कि हिन्दू राष्ट्र समर्थक दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से कितनी मदद ज्ञानेंद्र के लोगों को मिल रही है, लेकिन नैतिक समर्थन मिलने से कोई इंकार नहीं कर सकता। विगत शुक्रवार को जो कुछ काठमांडो में हुआ, वो वीभत्स और विनाशकारी था। उस दिन टिंकुने में राजभक्तों का प्रदर्शन हिंसा में परिवर्तित हो गया, जब दुर्गा प्रसाई जीप दौड़ाकर सुरक्षाकर्मियों और प्रत्यक्षदर्शियों को कुचलने की कोशिश करने लगे। हिंसक भीड़ ने जड़ीबूटी प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन कंपनी के आठ वाहनों को जला दिया, सीपीएन (एकीकृत समाजवादी) के मुख्यालय में आग लगा दी। कोटेश्वर में उन्होंने भटभटेनी सुपरमार्केट को लूट लिया, और जमकर तोड़फोड़ की। उग्र भीड़ ने पत्रकार सुरेश रजक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उनकी वहीं झुलसकर मौत हो गई। पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान सबिन महर्जन की गोली लगने से मौत हो गई। एक बात तो है, नेपाल में लोग लगातार विफल गवर्नेंस से ऊबे हुए हैं। इसका दुष्परिणाम तो आना था। राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) के डॉ. दुर्गा प्रसाई, 87 वर्षीय नवराज सुवेदी समेत 52 नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ज्ञानेंद्र की सुरक्षा कम कर दी गई, पासपोर्ट ज़ब्त है। इस तांडव के बाद भी राजा समर्थकों ने आगामी दो हफ्ते देशव्यापी प्रदर्शन, और 20 अप्रैल को राजधानी में आंदोलन की घोषणा की है। राजा समर्थकों को लगता है, लोहा गरम है, इसलिए आंदोलन की धार बनाये रखो। मंगलवार को आरपीपी केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष राजेंद्र लिंगडेन के नेतृत्व में राजतंत्र की बहाली के लिए अपने अभियान को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। राजेंद्र लिंगडेन के साथ पूर्व प्रजातंत्रवादी कमल थापा कन्धा मिलाने लगे हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष रवींद्र मिश्रा को सदस्य-सचिव नामित किया गया है। राजा समर्थक शीर्ष समूह में आरपीपी नेता पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चंद्र लोहानी सदस्य हैं। लेकिन, ये दोनों 'बूढ़े घोड़े' अब राजशाही की मशाल को आगे बढ़ाने की ताकत नहीं रखते हैं। फिर भी, पार्टी के नेताओं में लीड लेने की रेस लग गई है। चुनांचे, आरपीपी विभाजन की ओर भी बढ़ रही है। लेकिन, ये सारे उपक्रम करने के बाद, 80 की उम्र छूने वाले ज्ञानेंद्र सत्ता का सुख भोग भी पाएंगे? उनके बेटे, पारस की छवि एक लापरवाह, 'ड्रग एडिक्ट', गंभीर रूप से बीमार राजकुमार की है। ज्ञानेंद्र के पोते हृदयेंद्र ने अभी-अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है, और उन्हें शासन कला का प्रशिक्षण तक नहीं मिला है। नेपाल में हिन्दू राष्ट्र की वापसी भी होती है, तो वहां का 'मोदी' कौन होगा? ये तमाम सवाल, विक्रम के कंधे पर वेताल जैसे हैं।

आप का नजरीया

संघ-भाजपा में तालमेल

भले ही प्रसंग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सौ साल पूरा होने का हो, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की संघ के मुख्यालय की पहली यात्रा के गहरे निहितार्थ भी हैं। जो इस बात का संकेत है कि पिछले आम चुनाव के दौरान संघ व भाजपा के रिश्तों में जिस खटास की बात कही जा रही थी, वह संवाद व संपर्क से दूर कर ली गई है। जो इस बात का भी संकेत है कि आने वाले वक्त में पार्टी व सरकार के अहम फैसलों में संघ की भूमिका बढ़ सकती है। यूं तो प्रधानमंत्री ने बीते रविवार को नागपुर यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी की, लेकिन उनका प्रधानमंत्री के रूप में संघ मुख्यालय पहुंचना खास चर्चा में रहा। उल्लेखनीय है कि चौथाई सदी पहले संघ मुख्यालय पहुंचने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। साथ ही वे संघ की रीति-नीतियों से भली-भांति परिचित हैं। लेकिन पिछले आम चुनाव के दौरान भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ऐसे बयान चर्चाओं में थे कि पार्टी का कद संघ से बड़ा हो गया है। जिसके चलते संघ व भाजपा के रिश्तों में कुछ कसक देखी गई। जिसकी कुछ इस तरह व्याख्या की गई कि पार्टी जिस तरह चार सौ पार के लक्ष्य से चूकी, उसके मूल में संघ कार्यकर्ताओं की उदासीनता रही है। बाद में दोनों के रिश्ते सामान्य होने के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो आशातीत सफलता हाथ लगी, कहा जा रहा था कि उसमें संघ कार्यकर्ताओं का समर्पण व योगदान महत्वपूर्ण घटक रहा। अब संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री की यात्रा से यह तथ्य भी उजागर हुआ कि दोनों की रीतियों-नीतियों फिर से बेहतर तालमेल स्थापित हुआ है। अब राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के फैसलों में संघ के दृष्टिकोण का प्रभाव नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में संघ की भूमिका हो सकती है। ऐसा ही असर बदलते वक्त के साथ पार्टी के अन्य फैसलों पर भी नजर आ सकता है। यानी दोनों अब सामंजस्य व सहजता के साथ आगे बढ़ेंगे। अर्थात पार्टी अब अपने वैचारिक स्रोत के साथ बेहतर तालमेल करके चलना चाहेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने संघ मुख्यालय में कहा कि संघ का विचार बीज अब वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उन्होंने संघ कार्यकर्ताओं के योगदान की चर्चा करते हुए संघ को भारतीय संस्कृति का विशाल वट वृक्ष बताया। बहरहाल, भाजपा संघ से कुछ मुद्दों पर असहमति से आगे निकल चुकी है। उल्लेखनीय है कि आम चुनाव परिणाम के बाद संघ प्रमुख ने नसीहत दी थी कि लोगों की सेवा करने वाले एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी कतिपय उन नेताओं की तरफ इशारा भी था जिन्होंने कहा था कि पार्टी बड़ी हो गई है और उसे संघ की पहले की तरह जरूरत नहीं है। इसके बाद संघ ने अपने महत्व का अहसास पार्टी को कराया। जिसका राजनीतिक लाभ भाजपा को कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिला भी।

पंजाब सरकार ने नशे के विरुद्ध लुधियाना से शुरू किया अभियान

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तथा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को लुधियाना में हजारों युवाओं को शपथ दिलाने के बाद इस खतरे के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाई। नशे की समस्या के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मार्च पास्ट के लिए आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह नशे के खिलाफ निर्णायक जंग है और हम पूरे राज्य से इस अभिशाप को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही नशों की सप्लाई लाइन तोड़ दी है और इस घृणित अपराध में शामिल बड़े मगरमच्छों को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों द्वारा गैर-कानूनी तरीकों से बनाई गई संपत्ति को सरकार ने पहली बार ढहाया या जब्त किया है ताकि यह दूसरों को इस काम में आने से रोके। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के निरंतर नेतृत्व में पंजाब जल्द ही नशों के खतरे से मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ जंग को जन आंदोलन में बदला जाएगा क्योंकि यह सिर्फ पुलिस की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि अब लोग इस अभियान के लिए आगे आ रहे हैं और कई गांवों की पंचायतें नशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही हैं। मान ने कहा कि राज्य सरकार ने इस जंग में लोगों का सहयोग लेने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 97791-00200 जारी किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चला रहे नशा तस्करों के बारे में कोई भी जानकारी इस व्हाट्सएप नंबर पर देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अब पंजाब पुलिस राज्य से नशे के खतरे को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की जरूरत है कि आम आदमी नशों के खिलाफ जंग में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब हर कोई नशे की बुराई के खिलाफ आगे आए और पैसा कमाने के लिए राज्य की पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे मुट्ठी भर तस्करों का नामो-निशान मिटा दे।

वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के हित में देशभर में बिल का हो रहा है स्वागत : मदन राठौड़

जयपुर (हिंस)। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का देशभर में स्वागत हो रहा है। अधिकांश मुस्लिम वर्ग के लोग इस संशोधन से खुश है, यह बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। इस बिल से किसी की भी हानि नहीं हो रही है। इस बिल संशोधन में यह प्रावधान भी किया गया है कि जो वक्फ की संपत्ति वर्तमान में उससे कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। वक्फ बिल संशोधन वर्तमान समय की मांग है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वक्फ की संपत्ति पर कई लोगों ने कब्जे कर रखे है। वक्फ की संपत्ति अल्लाह को दी गई है तो इसकी संपत्ति पर बाहुबली या मठाधीशों का कब्जा क्यों है। कुछ बाहुबली लोग इस संपत्ति का उपयोग करते हुए लाभ प्राप्त कर रहे है, जबकि मुस्लिम समाज को

इसका लाभ तक नहीं मिल रहा। वक्फ बिल संशोधन मुसलमानों के हित में है, गरीब मुसलमानों के भलाई के लिए इस धन का उपयोग किया जाएगा। जबकि अब तक बाहुबली ही इसका उपयोग कर रहे थे। राठौड़ ने बताया कि यह कैसा कानून है जो यह कहता है कि किसी भी संपत्ति को कह दो कि ये वक्फ की संपत्ति है और वो उसकी हो जाए, यह ठीक नहीं है। ईश्वर किसी से संपत्ति छीनना नहीं चाहता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि वक्फ बोर्ड के पास 23 राज्यों और 7 संघ राज्यों में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। इन बोर्ड के पास कुल रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की संख्या 8.72 लाख और कुल क्षेत्रफल 37.39 लाख एकड़ का है, लेकिन उनकी आय के साथ साथ पारदर्शिता और सही प्रबंधन की कमी है। डिजिटलीकरण व जियो टैगिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और वक्फ संपत्तियों के सही इस्तेमाल से करीब 12,000 करोड़ से अधिक की सालाना आय संभव हो सकेगी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सही इस्तेमाल से होने वाली आय से देश के मुसलमान ही नहीं, बल्कि देश की भी तकदीर बदल सकती है।

कलश यात्रा पर पानी फेंकने से भूपालसागर में तनाव बाजार बंद, प्रशासन ने दिए कार्रवाई के निर्देश

चित्तौड़गढ़(हिंस)। जिले के भूपालसागर क्षेत्र में आयोजित धार्मिक महोत्सव की कलश यात्रा के दौरान गंदा पानी फेंकने की घटना से माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस घटना के विरोध में कस्बेवासियों ने आक्रोश जताते हुए बुधवार को बाजार बंद कर दिए और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भूपालसागर कस्बे में पांच दिवसीय धार्मिक आयोजन चल रहा है। मंगलवार को निकाली जा रही कलश यात्रा के दौरान समुदाय विशेष के एक व्यक्ति ने कथित रूप से गंदा पानी फेंक दिया, जिससे स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल आरोपी को हिरासत में ले लिया। बुधवार को कस्बे के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उपखंड अधिकारी पुनीत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों की बैठक में विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें

सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने का मुद्दा प्रमुख रहा। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सात दिनों के भीतर चारागाह और बिलानाम भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कस्बेवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांखला ने बताया कि जुलूस के दौरान हुई घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही, बाहरी शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है, और आवश्यकता पड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विकसित भारत के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव आवश्यक : सतीश पूनिया

नारनौल (हिंस)। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि) महेंद्रगढ़ में बुधवार को एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर केंद्रित पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव मौजूद रहे। मुख्य अतिथि सतीश पूनिया ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण हेतु एक राष्ट्र एक चुनाव आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों हरियाणा विधान सभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों से जब इस विषय पर संवाद किया तो उनका मत भी एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह विषय पुनः देश के समक्ष प्रस्तुत है। इस विषय पर निरंतर सकारात्मक चर्चा इसके मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में मददगार होगी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उल्लेख करते हुए देश में चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव का पक्ष लिया। विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि देश की मजबूती और संसाधनों के उचित इस्तेमाल के लिए आवश्यक है कि बार-बार विभिन्न स्तर पर होने वाली चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि निरंतर जारी रहने वाली चुनाव की यह प्रक्रिया सुशासन की दृष्टि से विभिन्न स्तर पर बाधाएं उत्पन्न करती है। इसलिए देश के विकास के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हुए शुरुआती चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत ही हुए थे। वर्ष 1967 के बाद विभिन्न कारणों से यह प्रक्रिया बदल दी गई। उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर एक साथ विभिन्न स्तर के चुनावों का आयोजन थोड़ा जटिल होगा लेकिन यह मुमकिन है और यकीनन देश हित में भी है। उन्होंने कहा कि भारत सदैव से ही विविधता में एकता का देश रहा है इसलिए सुशासन के लिए आवश्यक है कि प्रशासन विभिन्न स्तरों पर निरंतर चुनावों से इतर विकास के लिए प्रयासरत हो।

अधिकारी उन्हीं से एमओयू करें, जो फोन उठाए : गहलोत

राइजिंग राजस्थान में निवेश को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तंज कसा

जयपुर (हिंस)। राइजिंग राजस्थान में निवेश को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तंज कसत हुए कहा कि मैंने पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी कि जितना प्रचार कर रहे है उतना निवेश नहीं हो पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार ने खूब प्रचार किया था। विदेशों के दौरे किए और 33 लाख करोड़ के एमओयू होने के दावे किए। अगर उनमें से 10- 12 हजार करोड़ भी आते है तो हम इसका स्वागत करेंगे कि निवेश कुछ आया लेकिन, अब मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं कि निवेशक फोन नहीं उठा रहे, ईमेल का जवाब नहीं दे रहे है। आगे से अधिकारियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं से एमओयू करे, जो फोन उठाए। झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बुधवार को युवा कांग्रेस की ओर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस फेयर में 186 से अधिक बड़ी कंपनियां हिस्सा

ले रही हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब भी मौजूद थे। यहां पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि मैंने तो पहले से ही इसकी आशंका व्यक्त कर दी थी कि जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है उतना निवेश नहीं हो पाएगा। रोजगार मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की सरकारों ने युवाओं से रोजगार के खूब बड़े-बड़े वादे किए लेकिन रोजगार नहीं दिया। उन्होंने युवा कांग्रेस के इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अच्छी बात है कि युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी के संदेश को अमली जामा पहनाया है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे रोजगार मेले गली गली में लगने चाहिए। बड़ी-बड़ी कंपनियां आई हैं और लोगों को हाथों-हाथ रोजगार मिल रहा है। रोजगार मेले में 10वीं, 12वीं से लेकर उच्च शिक्षा तक के बेरोजगार युवाओं का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इंटरव्यू के बाद चयनित उम्मीदवारों को तुरंत ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं। आयोजकों का दावा है कि पहले चरण में करीब 2000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल पर पूछे गए सवालों पर नेताओं ने कहा कि बिल पेश होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व जवाब देगा।

किडनैप पुलिसकर्मियों को छुड़ाने पहुंचे थानाधिकारी का सिर फोड़ा, 11 घायल-गाड़ियां भी तोड़ीं

सीकर (हिंस)। अजीतगढ़ थाने के डाला वाली ढाणी में मंगलवार रात बंधक पुलिसवालों को छुड़ाने पहुंची पांच थानों की पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में सब थानाधिकारी और सब इंस्पेक्टर का सिर फूट गया और 11 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर घायल हुए हैं। आरोपितों ने पुलिसकर्मियों के गाड़ियों को भी तोड़ दिया। हमले की सूचना मिलने पर एसपी भुवन भूषण यादव भी मौके पर पहुंचे। इस मामले में पुलिस ने बुधवार सुबह तक करीब 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम अजीतगढ़ थाने के तीन पुलिसकर्मी मारपीट केस के फरार आरोपी महिपाल को पकड़ने गए थे। इसी दौरान गांव में आरोपी के ही

किसी परिचित की बारात निकल रही थी। ऐसे में बारात में शामिल लोगों ने तीनों को बंधक बना लिया। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो देर रात पांच थानों खंडेला, श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़, थोई, रींगस के 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी इन्हें छुड़ाने ढाणी में पहुंचे थे। पुलिस टीम को देखते ही ग्रामीणों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान गांव की कुछ महिलाओं ने भी पुलिस के साथ मारपीट की। घटना में अजीतगढ़ थानाधिकारी मुकेश सेपट, खंडेला थानाधिकारी इंद्रप्रकाश यादव समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुकेश सेपट के सिर में सात टांके आए हैं। माहौल बिगड़ता देख आरएसी की टीम को बुलाया गया।

केंद्र सरकार की सांध्यकालीन अदालतें चलाने की योजना को अमल में लाने के प्रयास शुरू

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने यूपी के सभी जिला जजों को पत्र भेजकर बार एसोसिएशनों से मांगा फीड बैक

प्रयागराज (हिंस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक ने केंद्र सरकार की सांध्यकालीन अदालत गठित करने की योजना को अमल में लाने से पहले संबंधित सभी लोगों खासकर वकीलों की राय व फीडबैक की रिपोर्ट मांगी है। महानिबंधक की तरफ से सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों व विशेष कार्याधिकारियों को पत्र लिखकर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जारी पत्र में प्रदेश के जिला अदालतों के सभी बार एसोसिएशनों को पत्र भेजकर उनसे भी सांध्यकालीन कोर्ट चलाने को लेकर फीड बैक लेने को कहा गया है। प्रस्तावित सांध्यकालीन अदालतें चलाने का उद्देश्य कम खर्च में सेवानिवृत्त जजों व स्टाफ की मदद से वर्तमान सुविधाओं के साथ छोटे मोटे मामलो का निपटारा करना है। इसमें छोटे आपराधिक मामले, संक्षिप्त विचारण व चेक अनादर केसों की सुनवाई होगी। अदालतें शाम पांच बजे से नौ बजे चार घंटे तक चलेगी। सकारात्मक सुझाव आने के बाद केंद्र सरकार की सांध्यकालीन अदालत चलाने की योजना को अमल में लाया जा सकेगा। सेंटर फार कांस्टीट्यूशनल एंड सोसल रिफार्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अधिवक्ता ए एन त्रिपाठी ने इस योजना को अव्यवहारिक करार देते हुए कहा है कि योजना रिटायरमेंट के बाद जजों को उपकृत करने व बेरोजगार युवा शक्ति में निराशा फैलाने वाली साबित होगी। योजना लक्ष्य हासिल कर सकेगी इसमें भारी संदेह है। त्रिपाठी ने कहा न्यायपालिका जनतंत्र का एक मजबूत स्तम्भ है। इस पर आपसी विवादों व कानूनी मुद्दे तय करने की जिम्मेदारी है। अपराधी को दंडित कर निर्दोष को बरी करने की जिम्मेदारी है। वर्तमान तंत्र को सही तरीके से चलाने में विफल रहने वाले सिस्टम का यह एक शिगूफा है। योजना न्याय देने की खानापूर्ति मात्र बनकर रह जायेगी। इन अदालतों में वकालत करने वाले वकीलों का ध्यान नहीं रखा गया है। सुबह नौ बजे से रात दस बजे तक काम करने के बाद अधिवक्ता किस लायक बचेंगे, इसका ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में ट्रायल एंड एरर की पद्धति अपनाना न्याय हित नहीं है। यह वादकारी का हित सर्वोच्च के सिद्धांत के विपरीत है। जिला अदालतों में जजों की समय से नियुक्ति नहीं की जाती। सैकड़ों की संख्या में पद वर्षों से खाली पड़े रहते हैं। सेवानिवृत्त जजों की सेवा लेना और युवा वकीलों को जज बनने का अवसर न देने का औचित्य नहीं है।

अकाली दल नेता मजीठिया की सुरक्षा वापस नहीं ली गई सिर्फ घटाई : पंजाब पुलिस

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब पुलिस ने बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा पूरी तरह से वापस लेने संबंधी रिपोर्टों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि खतरे के पुनर्मूल्यांकन के मद्देनजर उनके सुरक्षा कवच को सिर्फ घटाया गया है, वापस नहीं लिया गया। बुधवार को पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा समीक्षा समिति की नवीनतम सिफारिशों के बाद यह समायोजन/रद्दो-बदल किया गया था। प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी प्रमुख व्यक्ति की सुरक्षा की समय-समय पर संभावित खतरे के मूल्यांकन के आधार पर समीक्षा की जाती है। इस आधार पर सुरक्षा कवच को बढ़ाया या घटाया जाता है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बिक्रम मजीठिया के पास अभी भी पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश के 10 लाख लाभार्थियों ने दूसरे राज्यों में कराई अपनी ई-केवाईसी

लखनऊ (हिंस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले आठ वर्षों में गरीब और जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की प्रक्रिया को न केवल प्रभावी बनाया है, बल्कि इसे डिजिटल तकनीकों के माध्यम से पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त भी किया है। *सेवा, सुरक्षा और सुशासन* के मूल मंत्र को साकार करते हुए योगी सरकार ने खाद्य एवं रसद विभाग के जरिए तकनीकी नवाचारों को अपनाया, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के 1.15 करोड़ से अधिक राशन कार्डधारकों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली को लागू किया है। इसके तहत राशन कार्डधारकों को अब देश के किसी भी उचित दर दुकान पर ई-केवाईसी कराने की सुविधा प्राप्त हो रही है। खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के अनुसार मार्च -25 तक प्रदेश के 77.37 प्रतिशत लाभार्थियों (1,15,37,940 राशन कार्डधारक) ने अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है। खास बात यह है कि 10.02 लाख लाभार्थियों ने अन्य राज्यों में भी अपनी ई-केवाईसी कराई, जो इस व्यवस्था की व्यापक पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। यही नहीं इस डिजिटल पहल ने अपात्र कार्डधारकों की पहचान कर उन्हें सिस्टम से हटाने में मदद की, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों तक खाद्यान्न पहुंच सुनिश्चित हुआ। योगी सरकार का लक्ष्य शत-प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी शीघ्र पूरी करना है, ताकि वितरण प्रणाली और अधिक मजबूत हो सके। खास बात यह है कि राशन वितरण में ई-पॉस मशीनों के उपयोग ने पारदर्शिता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इन मशीनों के जरिए खाद्यान्न का वितरण सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जिससे बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगा है। यह तकनीकी नवाचार न केवल समय पर राशन उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सशक्त बनाने के लिए उचित दर दुकानों को आधुनिक रूप देने की पहल की है। इसके तहत *अन्नपूर्णा भवन* का निर्माण मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

बिहार को वर्ष 2070 तक कार्बन-फ्री बनाने का लक्ष्य

जलवायु परिवर्तन से निपटने को मास्टर प्लान तैयार

पटना (हिंस)। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बिहार सरकार तेजी से सराहनीय कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विशेष पहल पर राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए खासतौर से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। इसे लेकर संबंधित विभाग ने खासतौर से योजना तैयार की है। ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से जल-जीवन-हरियाली योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार क्लाइमेट रेसिलिएंट एंड लो-कार्बन डेवलपमेंट पाथ-वे नामक रणनीति दस्तावेज तैयार कर रही है। इस दस्तावेज में वर्ष 2030 और 2050 तक किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई है। ताकि विकास कार्यों से समझौता किए बगैर वर्ष 2070 तक बिहार कार्बन-फ्री बन सके। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने वर्ष 2021 में एक समझौता (एमओयू) किया था। इसके तहत जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन किया गया। तीन वर्षों की विभिन्न बैठकों के बाद इस एक्शन प्लान को अंतिम रूप दिया गया है, जिसे अब राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बिहार में कुल 4,316 आर्द्रभूमियां (वेटलैंड) हैं, जिनका संरक्षण एवं प्रबंधन आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत किया जाता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की कितनी जल निकायों को आर्द्रभूमि के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। बिहार सरकार मनरेगा के तहत जल निकायों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही कृषि विभाग पानी की खपत को कम करने के लिए मोटे अनाज, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर तकनीक को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और कई जिलों में आर्सेनिक और अन्य प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके समाधान के लिए सरकार कृषि वानिकी को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना और मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना चलाई जा रही है, जिससे अधिक से अधिक पौधे लगाए जा सकें।

ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, शोभायात्रा निकाली

वर्ष में एक बार खुलता है दरबार, शंखनाद, डमरू वादन और मंत्रोच्चार से पूरा धाम परिक्षेत्र गुंजायमान

वाराणसी (हिंस)। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर स्थित माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए विभिन्न संगठनों के साथ श्रद्धालु महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए खुलने वाले माता के दरबार में दर्शन पूजन के लिए मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी महिलाओं व हिंदू पक्ष के पैरोकार,अधिवक्ताओं के साथ ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ता भी पहुंचे। दरबार में श्रद्धालु महिलाओं ने विधि विधान से माता का दर्शन कर श्रृंगार सामग्री अर्पित कर उनसे सौभाग्य का आर्शीवाद मांगा। इसके पहले वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के नेतृत्व में मैदागिन स्थित गोरखनाथ मठ मां श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए शोभायात्रा यात्रा निकाली गई। इसमें चारों वादिनी महिलाएं भी शामिल हुई। श्रृंगार गौरी केस के मुख्य अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों को बताया कि हम मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उनके चरणों में हम कामना करेंगे कि जो न्यायालय में संघर्ष चल रहा है, उसमें विजय प्रदान करें। इसी क्रम में ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद

के जत्थे ने भी माता रानी की आरती उतारी। इस दौरान ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। श्रद्धालुओं को सत्यनारायण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर चार-बी से सुबह 8.30 बजे से प्रवेश दिया गया। दर्शन पूजन में महिला दर्शनार्थियों को वरीयता दी गई, जिससे उनकी लाइन आगे रही। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के बैनर तले श्रद्धालुओं का दल कलश में गंगा जल लेकर मंदिर में पहुंचा। *हर-हर महादेव* के गगनभेदी उद्घोष, शंखनाद, डमरू वादन और मंत्रोच्चार से पूरा धाम परिक्षेत्र गुंजायमान रहा। श्रद्धालुओं ने मां श्रृंगार गौरी की प्राचीन प्रतिमा के टूटे पत्थरों पर सिंदूर और चंदन का लेपन किया। इसके बाद पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया। पुजारियों ने वैदिक मंत्रों के साथ माता की आराधना की। इसी क्रम में चौक चित्रा सिनेमा के पास से भी श्रद्धालुओं की भीड़ गुलशन कपूर के नेतृत्व में दर्शन पूजन के लिए ज्ञानवापी पहुंचा। श्रद्धालु हाथों में पूजन सामग्री, माला फूल, ध्वज लेकर दरबार में पहुंचे। श्रद्धालुओं ने ज्ञानवापी कूप के जल से माता के विग्रह को स्नान कराया। फिर गुलाब, अड़हुल, बेला के फूलों से श्रृंगार कर माता को सिंदूर अर्पित किया। इसके बाद माता रानी से भव्य मंदिर बनने की गुहार लगाई। माता श्रृंगार गौरी के दर्शन के बाद दल ने ज्ञानवापी कूप के जल से काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। माता अन्नपूर्णा और ढुढ़ीराज गणेश का दर्शन कर जत्थे ने ज्ञानवापी परिसर में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर दर्शन पूजन यात्रा को विराम दिया और वापस अपने घरों को लौटे। इसके पहले मंगलवार शाम को श्री काशी विश्वनाथ धाम के सभागार में ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद की बैठक हुई। इसमें माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन कार्यक्रम, ज्ञानवापी व्यास जी तहखाना और बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन की रूप रेखा बनी। इस बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र, मंदिर के डिप्टी एसडीएम शंभू शरण, पुलिस उपायुक्त, ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद से डॉ. ज्ञान प्रकाश मिश्र, अधिवक्ता अनघ शुक्ल, पतंजलि पांडेय आदि की उपस्थिति रहीं।

एसयूवी की मांग के बीच, इस साल मारुति की वैगनआर ने बेची सबसे ज्यादा गाड़ी

नई दिल्ली

एसयूवी गाड़ियां का चलन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की पुरानी गाड़ी वैगनआर ने फिर लोगों को चौंका दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में वैगनआर देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। उसने टाटा की पंच को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। पिछले वित्त वर्ष में देश में वैगनआर की बिक्री 1.98 लाख यूनिट रही जबकि टाटा की पंच 1.96 लाख यूनिट के साथ दूसरे नंबर पर रही। हुंडई की क्रेटा 1.94 लाख यूनिट के साथ तीसरे नंबर पर रही।

वैगनआर की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि टॉप 5 में ये अकेली छोटी गाड़ी है। बाकी सब एसयूवी या यूपी हैं। मारुति की अर्टिगा 1.90 लाख यूनिट के साथ चौथे और ब्रेजा 1.89 लाख यूनिट के साथ पांचवें नंबर पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि कई लोगों को लगता था कि हैचबैक गाड़ियां अब नहीं चलेंगी, लेकिन वैगनआर की बिक्री ने दिखा दिया कि अभी भी इस कैटगरी में दम है। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा देश है और यहां हर तरह के ग्राहक हैं। कुछ लोग हैचबैक गाड़ियों को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मारुति हर तरह की गाड़ियां बनाने और बेचने पर ध्यान दे रही है। इसमें एसयूवी भी शामिल हैं, जो कंपनी के लिए एक अहम क्षेत्र है।

उन्होंने कहा कि मारुति हर कैटगरी में गाड़ियां बेचती है। हम एसयूवी या किसी और कैटगरी को कम नहीं आंकते। हम ग्राहकों को विकल्प देकर उनकी पसंद को सीमित नहीं करना चाहते। बाजार में एसयूवी गाड़ियों की बहुत मांग है। पिछले कुछ साल में एसयूवी की बिक्री दोगुनी हो गई है। अब ये सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां हैं। इस साल में एसयूवी की बिक्री 54 फीसदी रहने का अनुमान है। इस दौरान कुल मिलाकर 43 लाख गाड़ियां बिकीं।

न्यूज ब्रीफ

745 करोड़ जुटाने आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने सेबी के पास जमा किए दस्तावेज

नई दिल्ली। आनंद राठी ग्रुप की ब्रोकरेज इकाई आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 745 करोड़ से ज्यादा पैसा जुटाने के लिए सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दोबारा दाखिल किया है। कंपनी ने पहली बार दिसंबर 2024 में डीआरएचपी दाखिल किया था। कंपनी की तरफ से दाखिल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक 5 के फेस वैल्यू वाले इस आईपीओ में पूरी राशि फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाई जाएगी। कंपनी, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के साथ परामर्श कर 149 करोड़ तक के प्री-आईपीओ प्लेसमेंट का विकल्प भी तलाश सकती है। यदि ऐसा प्लेसमेंट होता है, तो उस राशि को फ्रेश इश्यू से घटा दिया जाएगा। कंपनी फ्रेश इश्यू से जुटाई गई राशि में से 550 करोड़ अपने लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की जरुरतों और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए इस्तेमाल करेगी। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड और आनंद राठी एडवाइजर्स लिमिटेड को बुक-रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है, जबकि एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू का रजिस्ट्रार है। कंपनी के इक्विटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड 'आनंद राठी' ब्रांड के तहत ब्रोकिंग, मार्जिन ट्रेडिंग और वित्तीय उत्पादों के वितरण जैसी कई तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी खुदरा निवेशकों, हाई-नेट-वर्थ व्यक्तियों, अल्ट्रा- और संस्थागत ग्राहकों जैसे विविध वर्गों को अपनी सेवाएं देती है।

गैलेक्सी एक्सकव्हर 7 प्रो को बाजार में उतारने की तैयारी

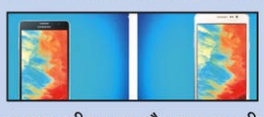

नई दिल्ली। साउथ कोरियाई कंपनी सैमसंग अपने नए रगेड स्मार्टफोन गैलेक्सी एक्सकव्हर 7 प्रो को लांच करने की तैयारी कर रही है। स्मार्टफोन का मॉडल नंबर एसएम-जी766यू और एसएम-जी766यू1 है। कंपनी को एफसीसी सर्टिफिकेशन मिलने के बाद इसके जल्द लॉन्च होने की संभावना बढ़ गई है। यह डिवाइस 2जी, 3जी, 4जी और 5जी नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। फोन को टीयूवी रेहइलैंड और गीकबेंच पर भी देखा जा चुका है, जिससे इसके संभावित स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हुआ है। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 7एस जेन 3 प्रोसेसर और अड्रीनो 810 जीपीयू के साथ आ सकता है। गीकबेंच टेस्टिंग में इसे 1157 सिंगल-कोर और 4265 मल्टी-कोर स्कोर मिले हैं। यह डिवाइस 6जीबी रैम के साथ लॉन्च हो सकता है और इसमें 4265एमएच बैटरी दी जा सकती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 बेस्ड वन यूआइई 7 पर काम करेगा। गैलेक्सी एक्सकव्हर 7 प्रो को लेकर अब तक आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह पिछले वेरिएंट गैलेक्सी एक्सकव्हर 7 का अपग्रेडेड वर्जन माना जा रहा है। पुराने मॉडल में 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस टीएफटी डिस्प्ले, आईपी68 वॉटर रेजिस्टेंस और एमआईएल-एसटीडी-810 एच सर्टिफिकेशन मिलता है। यह डाइमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर और 50एमपी प्राइमरी कैमरा के साथ आता है। इसमें 4050 एमएएच बैटरी, डॉल्बी ऐटमॉस साउंड, 3.5 एमएम हेडफोन जैक और यूएसबी-सी पोर्ट दिया गया है।

व्हाटसएप ने फरवरी में किए 97 लाख अकाउंट बैन, यूजर्स को दिए कई सुझाव

नई दिल्ली। मेटा के स्वामित्व वाली मशहूर मैसेजिंग ऐप व्हाटसएप ने कहा है कि फरवरी 2025 में भारत में 97 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। यह कार्रवाई व्हाटसएप के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के चलते की गई है। खास बात यह है कि इनमें से 14 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को यूजर्स की शिकायत से पहले ही बैन कर दिया गया था। यह जानकारी व्हाटसएप ने अपनी मासिक सुरक्षा रिपोर्ट में दी है, जो हर महीने जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में यूजर्स को सुरक्षित रखने और प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। व्हाटसएप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। साथ ही डेटा साइंटिस्ट्स और विशेषज्ञों की टीम भी इस काम में जुटी है। व्हाटसएप ने यूजर्स से अपील की है कि वे प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। इसके लिए कुछ आसान टिप्स भी शेयर किए हैं, जिसमें दूसरों की निजता का सम्मान करना, बार-बार मैसेज न भेजना और ब्रॉडकास्ट लिस्ट का सही तरीके से इस्तेमाल करना शामिल है।

ट्रंप के टैरिफ के पहले ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत, एशिया में मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान निचले स्तर से रिकवरी करने के बाद मजबूती के साथ बंद हुए थे। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार खरीदारी होती रही। वहीं एशियाई बाजारों में दबाव के बीच मिला-जुला कारोबार हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक रेसिप्रोकल टैरिफ देर रात लागू होंगे। इस टैरिफ के लागू होने के पहले दुनिया भर के निवेशकों की नजर नई अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी और ग्लोबल मार्केट पर उसके पड़ने वाले असर पर टिकी हुई है। इसी आशंका की वजह से दुनिया भर के बाजारों में असमंजस का माहौल बना हुआ है।

अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान दबाव में कारोबार करने के बाद निचले स्तर से रिकवरी करके बंद होने में सफल रहे। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.38 प्रतिशत की बढ़त के साथ 5,633.07 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 150.60 अंक यानी 0.87 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,449.89 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.08 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 41,955.51 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार भी पिछले सत्र के कारोबार के बाद मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। एफटीएसई इंडेक्स 0.60 प्रतिशत की मजबूती के साथ 8,634.80 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 1.09 प्रतिशत उछल कर 7,876.36 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 376.49 अंक यानी 1.67 प्रतिशत की जोरदार बढ़त के साथ 22,539.98 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशिया में मिला-जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एशिया के 9 बाजारों में से 5 के सूचकांक बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि 3 सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। इंडोनेशिया के स्टॉक एक्सचेंज में छुट्टी होने की वजह से जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में भी कोई बदलाव नहीं है। अभी तक के कारोबार में स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.26 प्रतिशत टूट कर 3,958.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह कोस्पी इंडेक्स 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,513.63 अंक के स्तर तक पहुंचा हुआ है। इसके अलावा ताईवान वेटेड इंडेक्स 0.01 प्रतिशत की सांकेतिक कमजोरी के साथ 21,279.02 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 103 अंक यानी 0.44 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,389 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.32 प्रतिशत उछल कर 1,171.71 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा निक्केई इंडेक्स 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 35,647.25 अंक के स्तर पर, हैंग सेंग इंडेक्स 0.06 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,220.15 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.24 प्रतिशत की मजबूती के साथ 3,356.41 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

मार्च में जीएसटी ने भरा सरकार का खजाना, 1.96 लाख करोड़ रुपए आए

नई दिल्ली

मार्च 2025 में जीएसटी का कुल संग्रह 9.9 फीसदी बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व 8.8 फीसदी बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि आयातित वस्तुओं से मिला राजस्व 13.56 फीसदी बढ़कर 46,919 करोड़ रुपए हो गया। मार्च में कुल रिफंड 41 फीसदी बढ़कर 19,615 करोड़ रुपए रहा है।

रिफंड को समायोजित करने के बाद मार्च 2025 में शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.76 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जो पिछले साल की तुलना में 7.3 फीसदी की बढ़ोतरी को दिखाता है। फरवरी 2025 में जीएसटी का कुल संग्रह 9.1 फीसदी बढ़कर करीब 1.84 ट्रिलियन रुपए था। आधिकारिक डेटा के मुताबिक सेंट्रल जीएसटी से 35,204 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी से 43,704 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपए और क्षतिपूर्ति उपकर से 13,868 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ था।

फरवरी में घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व 10.2 फीसदी बढ़कर 1.42 ट्रिलियन रुपए रहा था, जबकि आयात से राजस्व 5.4 फीसदी बढ़कर 41,702 करोड़ हो गया। फरवरी में जारी कुल रिफंड 20,889 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 17.3 फीसदी ज्यादा था। फरवरी 2025 में शुद्ध जीएसटी संग्रह 8.1 फीसदी बढ़कर करीब 1.63 ट्रिलियन रहा था। फरवरी 2024 में सकल और शुद्ध जीएसटी राजस्व क्रमशः 1.68 ट्रिलियन और 1.50 ट्रिलियन रुपए रहा। हालांकि, फरवरी 2025 में 1.84 ट्रिलियन रुपए का सकल जीएसटी संग्रह जनवरी 2025 में 1.96 ट्रिलियन रुपए के संग्रह से कम रहा।

रियलमी ने लांच किए रियलमी 14टी और सी75एक्स

रियलमी अपने दो नए स्मार्टफोन रियलमी 14टी और रियलमी सी75एक्स को बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने अभी तक इन डिवाइसेज की आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन ब्लूटूथ एसआईजी, एफसीसी और अन्य सर्टिफिकेशन साइट्स पर इन्हें देखा जा चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन जल्द ही मार्केट में एंट्री कर सकते हैं।

पीएलआई योजना : सरकार कंप्यूटर और सर्वर के आयात से हटाएगी प्रतिबंध

नई दिल्ली

अगर कंपनियां उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत देसी उत्पादन के वादे पर कायम रहती हैं तो सरकार लैपटॉप, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर सभी संभावित प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए तैयार है।

मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों ने जानकारी दी कि सभी प्रमुख लैपटॉप, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर डिवाइस एवं पुर्जा विनिर्माताओं ने से शुरू नए वित्त वर्ष में घरेलू मूल्यवर्धन को बेहतर करने के लिए अपनी योजनाएं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझा की हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन योजनाओं में स्थानीय उत्पादन बढ़ाना और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लैपटॉप केसिंग, स्पीकर, माइक्रोफोन, डिस्प्ले आदि इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जो की सोर्सिंग करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर साल के मध्य में उसकी समीक्षा की जाएगी और ऑडिट किए जाएंगे। इन सभी कंपनियों ने अपनी योजनाओं और समय-सीमाओं के बारे में जानकारी दी है। हम इसे एक संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं और प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने पर विचार करने को तैयार हैं। अगर ये कंपनियां अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं तो फिर कारणों पर गौर किया जाएगा और समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें सरकार क्या कर सकती है।

स्विगी को मिला 158 करोड़ का टैक्स मांग का नोटिस, उल्लंघनों से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली

फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने कहा है कि उसे अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए 158 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त टैक्स मांग वाला एक असेसमेंट ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बताया कि यह आदेश आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर, सेंट्रल सर्कल1, बेंगलुरु द्वारा जारी किया है।

यह मामला कथित उल्लंघनों से जुड़ा हुआ है, जिसमें मर्चेंट्स को दिए गए कैंसलेशन चार्ज को इनकम टैक्स एक्ट के तहत अस्वीकार किया जाना और इनकम टैक्स रिफंड पर मिले ब्याज को कर योग्य आय में शामिल न करना शामिल है।

स्विगी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, कंपनी को अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए एक असेसमेंट ऑर्डर मिला है, जिसमें 1,58,25,80,987 रुपए की अतिरिक्त आय जोड़ी गई है।

कंपनी ने कहा कि आदेश के खिलाफ मजबूत तर्कों पर भरोसा है और वह अपनी स्थिति की रक्षा के लिए अपील के जरिए जरूरी कदम उठा रही है। कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है इस आदेश का उसकी वित्तीय स्थिति और संचालन पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्विगी 13 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी। बाजार में कदम रखने के बाद से फूड डिलीवरी कंपनी के शेयरों पर दबाव देखा गया है। पिछले तीन महीनों में कंपनी के शेयर 38.88 फीसदी तक गिरे हैं। पिछले कारोबारी सत्र 1 अप्रैल में स्विगी का शेयर 0.50 फीसदी की तेजी लेकर 331.55 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ।

गरीबी में बीता होंडा मोटर्स के संस्थापक साइचिरो का बचपन

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक होंडा मोटर्स के संस्थापक साइचिरो होंडा का सफर संघर्षों से भरा रहा है। जापान के एक छोटे से गांव में 1906 में जन्मे साइचिरो का बचपन बेहद गरीबी में बीता। उनके पिता साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, जबकि उनकी मां कपड़ा बुनती थीं। पढ़ाई में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन मशीनों के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और टोक्यो जाकर 'आर्टशोकाई' कंपनी में मैकेनिक बनने की कोशिश की। वहां उन्हें शुरुआत में झाड़ू-पोंछा करने का काम मिला, लेकिन उन्होंने इसे सीखने के अवसर के रूप में लिया और जल्द ही कार रिपेयरिंग में माहिर हो गए। 1991 में उनके निधन के समय, होंडा मोटर्स दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन चुकी थी। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि मेहनत और लगन से कोई भी इंसान असंभव को संभव बना सकता है। साइचिरो होंडा ने रेसिंग कार डिजाइन की, जिसने 1924 की जापानी मोटर कार रेस में पहला स्थान प्राप्त किया। लेकिन 1936 में एक रेसिंग प्रतियोगिता के दौरान हुए हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उनका रेसिंग करियर समाप्त हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया और पिस्टन रिंग बनाने का व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में उनके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा कोशिश की। आखिरकार, उनकी पिस्टन रिंग्स को टोयोटा ने स्वीकार कर लिया और उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ा।

उत्तर मध्य रेलवे की महिला हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक, पुरुष जिम्नास्टिक टीम ने प्राप्त किया तीसरा स्थान

प्रयागराज

मार्च के अंतिम सप्ताह में आयोजित अंतर रेलवे प्रतियोगिताओं में उत्तर मध्य रेलवे के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ज़ोन को गौरवान्वित किया। उत्तर मध्य रेलवे की टीमों और खिलाड़ियों को महाप्रबंधक उत्तर उपेंद्र चंद्र जोशी ने शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी वे उत्तर मध्य रेलवे और राष्ट्र के लिए इसी तरह उपलब्धियां हासिल करेंगे।

वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि 22 से 28 मार्च तक एमसीएफ रायबरेली (यूपी) में आयोजित अंतर रेलवे महिला हॉकी चैम्पियनशिप में उत्तर मध्य रेलवे की टीम ने कांस्य पदक जीता। टीम की कोच नीलम व मैनेजर रचना चौरसिया थीं। गुरजीत कौर और निशा वारसी सहित अन्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों से सज्जित उत्तर मध्य रेलवे की महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक मैच में पिछली बार की चैम्पियन साउथ ईस्टर्न रेलवे को 5-3 से हराया।

उन्होंने बताया कि इसी क्रम में 28 से 30 मार्च तक कोलकाता में आयोजित अंतर रेलवे जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में उत्तर मध्य रेलवे की टीम ने टीम चैम्पियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

इस टीम के कोच देवेंद्र झा और सहायक कोच देवेश थे। प्रतियोगिता में आदित्य सिंह राणा टूर्नामेंट के ऑल राउंड बेस्ट जिम्नास्ट और अंकुर शर्मा टूर्नामेंट के ऑल राउंड दूसरे बेस्ट जिम्नास्ट बने।

आदित्य सिंह राणा ने फ्लोर में रजत और रिंग्स में स्वर्ण पदक, आशीष कुमार ने फ्लोर में स्वर्ण, सिद्धार्थ वर्मा ने पॉमेल हॉर्स में गोल्ड और अंकुर शर्मा ने पैरेलल बार में रजत पदक प्राप्त किया।

इसके अलावा 24 से 26 मार्च तक वाराणसी के बीएलडब्ल्यू में आयोजित इंटर रेलवे गोल्फ चैम्पियनशिप में उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में कार्यरत अमित कुमार ने रजत पदक जीता। इवेंट में इनका स्कोर 36 होल में 4 अंडर स्कोर रहा। इस अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे खेल संघ के अध्यक्ष एसपी द्विवेदी, उपाध्यक्ष बीपी सिंह, महासचिव सर्वेश चंद द्विवेदी, सचिव-महाप्रबंधक अजय सिंह, उत्तर मध्य रेलवे खेल संघ के संयुक्त सचिव डॉ. अमित मालवीय उपस्थित रहे।

न्यूज ब्रीफ

भारतीय तीरंदाजी टीम को अप्रैल में होने वाले विश्व कप चरण-1 के लिए नहीं मिला अमेरिकी वीजा

नई दिल्ली। भारतीय तीरंदाजी टीम ने घोषणा की है कि वह अमेरिकी वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है और संभवत: 8 से 13 अप्रैल तक फ्लोरिडा में होने वाले विश्व कप स्टेज-1 प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी। भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) ने खुलासा किया कि 16 सदस्यीय टीम को अप्रत्याशित सिस्टम मुद्दों के कारण वीजा अपॉइंटमेंट प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एएआई ने इंस्टाग्राम पर कहा, दुर्भाग्य से पिछले 40 दिनों में हमारे अथक प्रयासों और कई फॉलो-अप के बावजूद भारतीय तीरंदाजी टीम को अप्रत्याशित सिस्टम मुद्दों के कारण अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट प्राप्त करने में अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, हम आगामी विश्व कप प्रतियोगिता से बाहर होने के कगार पर हैं, जिसका हमारी भागीदारी और प्रतिस्पर्धी संभावनाओं पर गंभीर असर पड़ेगा। इस मुद्दे को हल करने और हमारी टीम के लिए संभावित झटके को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप जरूरी है। 2025 विश्व कप में पांच प्रतियोगिताएं शामिल हैं और यह 8 अप्रैल से 19 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें फ्लोरिडा, शंघाई, अंताल्या, मैड्रिड और नानजिंग मेजबान शहर होंगे। 2025 के लिए भारतीय टीम रिकर्व पुरुष: धीरज बोम्मदेवरा, तरूणदीप राय, अतनु दास और पार्थ सुशांत सालुंखे। रिकर्व महिला: अंकिता भक्त, दीपिका कुमारी, सिमरनजीत कौर और अंशिका कुमारी। कंपाउंड मैन: अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव, ओजस प्रवीण देवताले और उदय कंबोज। मिश्रित महिलाएं: मधुरा धमनगांवकर, ज्योति सुरेखा वेन्नम, तानीपर्थी चिकिथा और अदिति स्वामी।

हार के बाद लखनऊ की पिच पर फूटा जहीर खान का गुस्सा, कहा-ऐसा लग रहा था जैसे पंजाब के क्यूरेटर ने तैयार की हो

लखनऊ। आईपीएल 2025 में घरेलू मैदान की पिच से परेशान होने वाली टीमों की सूची में अब लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) भी शामिल हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद, अब एलएसजी भी अपने होम ग्राउंड की पिच से निराश नजर आई। टीम के मेंटॉर जहीर खान ने मंगलवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली 8 विकेट की हार के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसा लग रहा था मानो यहां पंजाब का क्यूरेटर काम कर रहा हो। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में एलएसजी को आठ विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद जहीर खान ने पिच को लेकर अपनी नाराजगी जताई। मैच के बाद जहीर खान ने कहा, यह थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि यह हमारा घरेलू मैदान है। आईपीएल में आपने देखा होगा कि टीमें अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहां क्यूरेटर ने इस बारे में नहीं सोचा। ऐसा लग रहा था जैसे यह पंजाब का क्यूरेटर था। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए भी एक नई जिम्मेदारी है, लेकिन उम्मीद है कि यह पहला और आखिरी मैच होगा जहां ऐसा हुआ। हमारे प्रशंसक हमें यहां जीतते हुए देखना चाहते हैं। हमें अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की जरूरत है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जहीर से पूछा गया कि क्या उन्होंने और कप्तान ऋषभ पंत ने पिच को गलत पढ़ा, तो उन्होंने जवाब दिया, देखिए, हम तो वही करेंगे जो क्यूरेटर कहेगा, नहीं इसे बहाने के रूप में नहीं ले रहे, लेकिन पिछले सीजन में भी हमने देखा कि यहां बल्लेबाजों को दिक्कत होती थी और गेंदबाज हावी रहते थे।

अब चेन्नई में होने वाले छह मैचों में ही नजर आयेंगे धोनी :फ्लेमिंग

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में इस बार चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और उसे एक ही मैच में जीत मिली है। टीम के मुख्य बल्लेबाज महेन्द्र सिंह धोनी भी लय में नहीं दिखते और निचले क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं। इसी को लेकर अब टीम के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने अहम खुलासा किया है। फ्लेमिंग ने कहा है कि फ्लेमिंग की फिटनेस अब पहले की तरह नहीं है और उनपर अधिक बोझ नहीं डाला जा सकता। इसलिए वह सत्र में केवल 6 मैच ही खेल सकेंगे। ये मैच चेन्नई में ही खेले जाएंगे। वहीं अन्य स्थानों पर होने वाले मैचों के लिए उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। फ्लेमिंग ने यह भी कहा कि धोनी के घुटने में समस्या है, जिससे वह पूरे 10 ओवर तक बल्लेबाजी नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का सहयोग करने के लिए भेजा जाएगा। ऐसे में उन्हें 9वें या 10वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा जा सकता। फ्लेमिंग ने हालांकि धोनी की नेतृत्व क्षमता और विकेटकीपिंग की जमकर प्रशंसा की है।

कोपा डेल रे सेमीफाइनल : रूडिगर बने हीरो, रियल मैड्रिड ने रियल सोसिएदाद को हराकर फाइनल में बनाई जगह

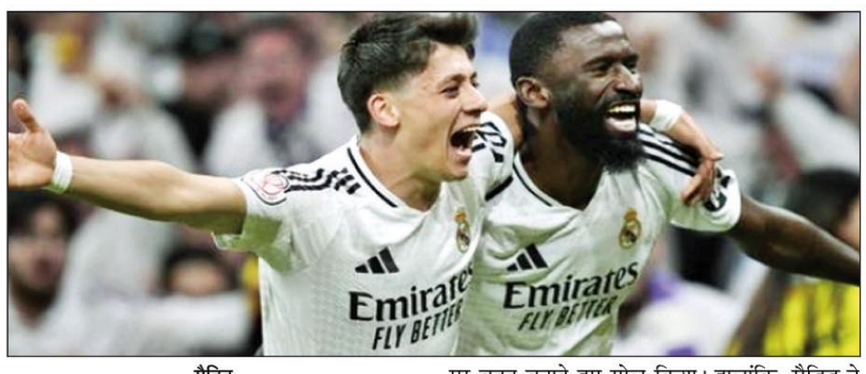

मैड्रिड

रियल मैड्रिड ने मंगलवार को रियल सोसिएदाद के खिलाफ रोमांचक 4-4 के ड्रॉ के साथ कोपा डेल रे के फाइनल में जगह बनाई, जिससे उसने कुल 5-4 के स्कोर के साथ सेमीफाइनल जीत लिया। एंटोनियो रूडिगर ने 115वें मिनट में हेडर के जरिए निर्णायक गोल किया, जिससे मैड्रिड अब फाइनल में बार्सिलोना या एटलेटिको मैड्रिड का सामना करेगा। पहले चरण में 1-0 से पिछड़ रही रियल सोसिएदाद ने एंडर बार्रेनचेया के गोल से बढ़त बनाई, लेकिन एंड्रिक के शानदार चिप शॉट से रियल मैड्रिड ने बराबरी कर ली। डेविड अल्बा के आत्मघाती गोल और मिकेल ओयारज़ाबल के डिफ्लेक्टेड शॉट से सोसिएदाद को बढ़त मिली, लेकिन मैड्रिड ने जूड बेलिंघम और ऑरेलियन चुआमेनी के गोलों से वापसी की। स्टॉपेज टाइम में दूसरा गोल कर मुकाबले को अतिरिक्त समय तक खींचा, लेकिन सोसिएदाद पेनल्टी तक मुकाबला नहीं ले जा सकी। अंतत: रूडिगर के हेडर ने मैड्रिड को फाइनल में पहुंचा दिया। मैड्रिड के कोच कार्लो एंसेलोटी ने विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो को शुरुआती लाइनअप में रखा, जबकि काइलियन एम्बाप्पे को आराम दिया और उनकी जगह एंड्रिक को मौका मिला। 18 वर्षीय एंड्रिक, जिन्होंने पहले चरण में एकमात्र गोल किया था, शुरूआती मिनटों में सक्रिय दिखे और एक शानदार ओवरहेड किक से गोल करने के करीब पहुंचे। बेलिंघम ने भी गोल करने की कोशिश की, लेकिन बढ़त रियल सोसिएदाद ने ली। बार्रेनचेया ने पाब्लो मारिन के पास पर बढ़त बनाते हुए गोल किया। हालांकि, मैड्रिड ने जल्द ही बराबरी कर ली। विनीसियस ने बाएं फ्लैंक से बेहतरीन थ्रू बॉल दी, जिस पर एंड्रिक ने शानदार लोब्ड फिनिश करते हुए गोल किया। सोसिएदाद ने पहले हाफ के अंत में पेनल्टी की मांग की, जब ताकेफुसा कुबो बॉक्स में विनीसियस से टकरा गए, लेकिन रेफरी ने इसे खारिज कर दिया। दूसरे हाफ में एंसेलोटी ने एंड्रिक की जगह एम्बाप्पे को मैदान पर उतारा, लेकिन मौके बनाने में सोसिएदाद अधिक सफल दिखी। गोलकीपर आंद्रिय लूनिन ने मार्टिन जुबिमेंडी का शानदार बचाव किया, लेकिन 72वें मिनट में मारिन के क्रॉस पर अलाबा का आत्मघाती गोल हुआ, जिससे सोसिएदाद को बढ़त मिली। इसके बाद ओयारज़ाबाल का डिफ्लेक्टेड शॉट लूनिन को छकाते हुए गोल में चला गया, जिससे सोसिएदाद की बढ़त और मजबूत हो गई। लेकिन इसके बाद मैड्रिड ने जोरदार वापसी की। 82वें मिनट में विनीसियस के पास पर बेलिंघम ने गोल किया और चार मिनट बाद चुआमेनी के हेडर पर गोलकीपर रेमिरो की गलती से स्कोर 4-4 हो गया। 90+3वें मिनट में ओयारज़ाबाल के हेडर से मुकाबला अतिरिक्त समय तक गया, लेकिन सोसिएदाद अंतिम क्षणों तक बढ़त नहीं बचा सकी। अंतत: 115वें मिनट में अरदा गुलर के कॉर्नर पर रूडिगर के बेहतरीन हेडर ने मैड्रिड को फाइनल में पहुंचा दिया। अब बुधवार को एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। दोनों टीमें पहले चरण में 4-4 की बराबरी पर हैं।

न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रनों से हराकर जीती सीरीज, तीसरे वनडे में क्लीन स्वीप का मौका

हैमिल्टन। न्यूजीलैंड ने बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हुए 84 रनों की जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली। अब कीवी टीम शनिवार को माउंट माउंगानुई में होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे में क्लीन स्वीप करने उतरेगी। बेन सियर्स का कहर, पहली बार लिया पांच विकेट मैच में न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी सफलता तेज गेंदबाज बेन सियर्स को मिली, जिन्होंने अपने तीसरे वनडे में ही पांच विकेट झटककर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। सियर्स ने अपने पहले दो वनडे में कोई विकेट नहीं लिया था, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने 59 रन देकर 5 विकेट झटके और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान की खराब शुरुआत, शुरुआती झटकों से नहीं उबर पाई टीम 293 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। विल ओरूर्के ने पहले ही ओवर में अब्दुल्ला शफीक (1) को आउट कर दिया। इसके बाद बाबर आजम भी सिर्फ 1 रन बनाकर जैकब डफी का शिकार बने। इमाम-उल-हक (0) भी डफी की गेंद पर आउट हुए,जिससे पाकिस्तान 5.3 ओवर में ही 9/3 के स्कोर पर संघर्ष कर रहा था। इसके बाद भी टीम की हालत नहीं सुधरी। सलमान आगा (9) के रूप में चौथा विकेट गिरा, जबकि कप्तान मोहम्मद रिजवान भी 27 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तैयब ताहिर (13), मोहम्मद वसीम (1) और अकिफ जावेद भी जल्दी आउट हो गए, जिससे पाकिस्तान की हार लगभग तय हो गई थी। हालांकि, फहीम अशरफ और नसीम शाह ने 60 रनों की साझेदारी कर कुछ संघर्ष दिखाया। अशरफ ने 80 गेंदों में 73 रन बनाए, जबकि नसीम शाह ने 44 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली। लेकिन उनकी ये पारियां न्यूजीलैंड की जीत को रोकने के लिए काफी नहीं थीं। न्यूजीलैंड के लिए बेन सियर्स ने 5 विकेट (5/59) लिए, जबकि जैकब डफी ने 3/35 का शानदार प्रदर्शन किया।

आईपीएल 2025: एलएसजी के गेंदबाज दिग्वेश सिंह पर लगा मैच फीस का 25प्रतिशत जुर्माना

नई दिल्ली

मंगलवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 मैच के दौरान एलएसजी के तेज गेंदबाज दिग्वेश सिंह को आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इसके चलते उन्हें उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना भरना होगा और साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है।

दिग्वेश ने पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रियांश आर्य को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कराया, आर्या डग-आउट की ओर जा रहे थे, तो दिग्वेश ने उनका पीछा किया और एक काल्पनिक नोटबुक पर लिखना शुरू कर दिया। हालांकि बल्लेबाज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली प्रीमियर लीग में दोनों ने एक ही टीम का प्रतिनिधित्व किया था। दिग्वेश की इस हरकत को आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन माना गया। दिग्वेश ने लेवल 1 अपराध के तहत अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करना स्वीकार किया और मैच रेफरी द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया। आचार संहिता के अनुसार, लेवल 1 के उल्लंघन के मामलों में मैच रेफरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। आईपीएल के नियमों के अनुसार, यदि किसी खिलाड़ी के चार डिमेरिट पॉइंट जुड़ जाते हैं, तो उन्हें एक मैच के लिए निलंबित किया जा सकता है। हालांकि, दिग्वेश पर अभी सिर्फ एक डिमेरिट पॉइंट लगा है, इसलिए उन्हें किसी निलंबन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आगे भी इस तरह की कोई घटना दोहराई जाती है, तो उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

आरसीबी बनी इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली आईपीएल टीम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने इंस्टाग्राम पर अपनी लोकप्रियता के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। टीम ने 18 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे वह इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी बन गई है। आरसीबी ने अपने अनोखे और आकर्षक कंटेंट के जरिए फैंस से गहरा जुड़ाव बनाया है, जिससे सोशल मीडिया उनके लिए ब्रांड ग्रोथ और कमर्शियल एंगेजमेंट का एक मजबूत जरिया बन गया है। यह जानकारी फ्रेंचाइजी द्वारा जारी एक बयान में दी गई। पिछले साल नवंबर 2023 तक आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और मुंबई इंडियंस (एमआई) से पीछे थी। हालांकि, टीम की प्रभावी सोशल मीडिया रणनीति और फैंस की जबरदस्त निष्ठा ने उसे इस रेस में आगे ला दिया। अब आरसीबी के 18.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि सीएसके के 17.8 मिलियन और एमआई के 16.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आरसीबी ने 23 मार्च को 17 मिलियन का आंकड़ा छुआ था और महज 10 दिनों में 18 मिलियन तक पहुंच गई। आरसीबी की सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के पीछे उनकी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ऐतिहासिक जीत भी एक बड़ी वजह रही। टीम ने 17 साल बाद सीएसके को उनके घरेलू मैदान पर हराया, जिससे फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर टीम को जबरदस्त सपोर्ट मिला और फॉलोअर्स की संख्या में तेजी आई।

शार्लेट एडवर्ड्स बनीं इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की नई हेड कोच

लंदन

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने मंगलवार को शार्लेट एडवर्ड्स को इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। पूर्व इंग्लैंड कप्तान एडवर्ड्स ने अपने देश के लिए 300 से अधिक मैच खेले हैं और अपने 20 साल के क्रिकेट करियर में दो वर्ल्ड कप और पाँच बार एशेज ट्रॉफी जीती है। 2017 में संन्यास लेने के बाद, एडवर्ड्स ने इंग्लिश घरेलू क्रिकेट और वैश्विक टी20 लीगों में कोचिंग की है। उन्होंने दक्षिणी वाइपर, द हंड्रेड में साउदर्न ब्रेव, विमेंस बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स और विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के साथ सफलता हासिल की है।

अपनी नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए एडवर्ड्स ने कहा, इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के नेतृत्व का फिर से हिस्सा बनने पर मैं बेहद रोमांचित हूं। इस टीम को आगे ले जाना और सफलता की ओर बढ़ाना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए फिर से तीन शेरों (इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम का लोगो) को धारण करना दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। इंग्लैंड की कप्तानी करना मेरे जीवन का अहम हिस्सा रहा है और मैं हमेशा इस टीम और इसकी विरासत के प्रति समर्पित रहूंगी। हमारे पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का एक बेहतरीन समूह है, और मैं उनके साथ काम करने और उन्हें व्यक्तिगत और टीम स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हूं।

उन्होंने आगे कहा, हमारे सामने दो घरेलू सीरीज का त्वरित चुनौती है, जिसके बाद इस साल के अंत में भारत में आईसीसी महिला विश्व कप खेला जाना है।

अगले साल इंग्लैंड में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप भी होगा और इसके बाद 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में महिला क्रिकेट की पहली उपस्थिति होगी। मैं इस टीम के साथ ट्रॉफी जीतने और इसे आगे ले जाने के लिए तैयार हूं।

ईसीबी की डिप्टी सीईओ और इंग्लैंड महिला क्रिकेट की मैनेजिंग डायरेक्टर क्लेयर कॉनर ने कहा, जब हमने इस पद के लिए मानदंड तय किए, तो यह जल्दी स्पष्ट हो गया कि शार्लेट एडवर्ड्स सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हैं।

उन्होंने आगे कहा, उनके पास अनुभव, जुनून और विशेषज्ञता है, जो इस टीम को सफलता की ओर ले जा सकती है। बतौर हेड कोच उन्होंने अलग-अलग टीमों के साथ बेहतरीन नतीजे दिए हैं। यह उनके निरंतर प्रयास और उच्च मानकों का प्रमाण है। वह एक सिद्ध विजेता हैं, जिन्होंने एक खिलाड़ी और अब कोच के रूप में लगातार सफलता हासिल की है।

शार्लेट एडवर्ड्स वर्तमान में हैम्पशायर से ईसीबी में शामिल हो रही हैं। इंग्लैंड महिला टीम की हेड कोच के रूप में उनका पहला मैच 21 मई को वेस्टइंडीज के खिलाफ कैंटरबरी में होगा। इंग्लैंड महिला टीम के नए कप्तान की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

वेस्ट इंडीज़ 1975 विश्व कप की ऐतिहासिक जीत की 50वीं वर्षगांठ मनाएगा

नई दिल्ली

वेस्ट इंडीज़ अपनी ऐतिहासिक 1975 विश्व कप जीत की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जिसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन में 21 जून 1975 को हासिल किया गया था। उस समय इसे प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप कहा जाता था। इस टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लाइव लॉयड की शानदार सेंचुरी ने वेस्ट इंडीज़ को 17 रन से जीत दिलाई थी और लॉयड ने ट्रॉफी उठाई थी।

वेस्ट इंडीज़ के इस ऐतिहासिक सम्मान समारोह का आयोजन बारबाडोस में होगा, हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने इस योजना का स्वागत करते हुए कहा, यह एक बेहतरीन विचार है। मैं विस्तार से तो नहीं जानता, लेकिन यह बहुत अच्छा है कि हम अपनी उपलब्धियों को मान्यता दे रहे हैं।

होल्डिंग, जो 1975 के विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा नहीं थे, 1979 और 1983 के विश्व कप में वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा रहे। 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज़ को फाइनल में हराया था।

होल्डिंग ने आगे कहा, सभी अन्य देश अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं और हमें भी अपनी कहानी लिखनी चाहिए और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। 1975 की विश्व कप जीत वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट इतिहास के सबसे महान क्षणों में से एक मानी जाती है, जो उनके विश्व क्रिकेट में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के समय पर आई। वेस्ट इंडीज़ का प्रभुत्व अगले दशक तक बना रहा, लेकिन उसके बाद टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई, और तब से वह पूरी तरह से वापस नहीं आ सकी है। सीडब्ल्यूआई के अध्यक्ष डॉ. किशोर शैलो ने हाल ही में मीडिया सम्मेलन में इस आयोजन की योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा, इस साल हम 1975 में हुई अपनी पहली विश्व कप जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम आयोजन के अंतिम चरण में हैं, कुछ चीज़ों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डॉ. शैलो ने स्पोर्ट्समैक्स वेबसाइट को बताया,यह हमारे वार्षिक कैलेंडर का एक प्रमुख हिस्सा होगा। इस जीत के 12 जीवित सदस्य हैं, और हम उनका सम्मान बारबाडोस में होने वाले इस समारोह में करेंगे। यह हमारे लिए एक शानदार आयोजन होगा, साथ ही हम अपनी घरेलू सीरीज का भी इंतजार कर रहे हैं, वर्तमान में जीवित 12 सदस्य हैं: गॉर्डन ग्रीनिज़ (73), अल्विन कालिचरन (76), रोहन कन्हाई (89), क्लाइव लॉयड (80), विव रिचर्ड्स (73), बर्नार्ड जूलियन (75), डेरेक मरे (81), वैनबर्न होल्डर (79), एंडी रॉबर्ट्स (74), कॉलिस किंग (73), लांस गिब्स (90) और मौरिस फोस्टर (81)। इस टीम के दो खिलाड़ी अब इस दुनिया में नहीं रहे – रॉय फ्रेडरिक्स (सितंबर 2000 में 57 वर्ष की आयु में निधन) और कीथ बॉयस (अक्टूबर 1996 में 53 वर्ष की आयु में निधन)।

दुनिया में हर साल 300 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक तैयार हो रहा है। हमारे जीवन में घुसपैठ कर चुके प्लास्टिक का एक खतरनाक पहलू यह है कि इससे तैयार कोई भी उत्पाद पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक को किसी भी तरीके से नष्ट या खत्म करने अथवा कहीं डंप करने के बावजूद उसका घातक असर पर्यावरण में मौजूद रहता है। प्लास्टिक कचरे को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए वैज्ञानिक पिछले कुछ दशकों से गंभीर प्रयासों में जुटे हैं और हाल ही में उन्हें इस दिशा में बड़ी सफलताएं भी मिली हैं।

प्लास्टिक को खत्म करने की जुगत...

अब पैसों से खरीदें खुशी...

पैसा जो काम की सारी चीजे दिला सकता है, लेकिन एक चीज नहीं दिला सकता, वो है खुशी। ऐसा बड़े बुजुर्गों का मानना था। लेकिन एक नए शोध ने इस कहावत को झुठला दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पैसे के सही इस्तेमाल से आप खुशियां भी खरीद सकते हैं। शोध में कहा गया है कि अगर आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार पैसा खर्च करते हैं, तो इससे आपको वास्तव में खुशी का अहसास होगा। साथ ही अपनी जरूरतों के मुताबिक खर्च करने से आपकी जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। ब्रिटेन स्थित कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के शोध में पता चला है कि पैसा और संपूर्ण व्यक्तित्व के बीच हमेशा से ही कमजोर संबंध रहा है। शोध वास्तविक लेन-देन के आंकड़ों को खंगालते हुए इस तथ्य की नई जमीन तैयार करता है कि खर्च हमारी खुशी को बढ़ा सकता है। बशर्ते इसका इस्तेमाल सही वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाए जो हमारे व्यक्तित्व के लिए उपयुक्त होने के साथ ही हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को भी पूरा करती हों।

तनाव कम करने में मददगार है चॉकलेट खाना

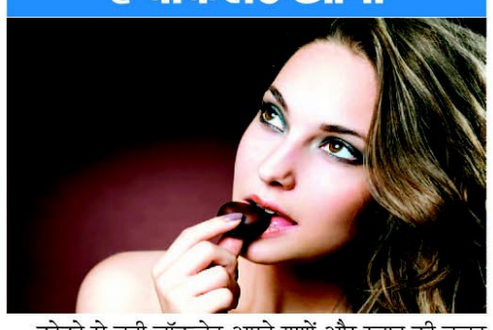

कोको से बनी चॉकलेट अपने गुणों और स्वाद की वजह से लगभग 100 सालों से ही टेस्टी ड्रिंक्स और चॉकलेट बार के रूप में फेमस रही है। चॉकलेट प्रेमी जानते हैं कि चॉकलेट मूड अच्छा रखने के साथ ही तनाव भी दूर करती है। इसके अलावा इसे खाने के और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं इनके बारे में जानेंगे...।

दिल के लिए लाभदायक

साल 2010 में हुए एक सर्वे से पता चला है कि यह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसलिए चॉकलेट खाने से दिल की बीमारियों के होने की संभावना काफी कम हो जाती है। वहीं यूरोपीय सोसायटी ऑफ कार्डियोलॉजी द्वारा किए गए शोध में पाया गया है कि ज्यादा मात्रा में चॉकलेट खाने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। मूड अच्छा बनाए चॉकलेटऑस्ट्रेलियाई रिसर्चर्स द्वारा साल 2015 में किए गए स्टडीज के अनुसार, कोको का इस्तेमाल हेल्दी लोगों में शांति और संतोष बढ़ाता है। इसके अलावा यह मेंटली परफॉर्मेंस को बेहतर कर थकान कम करने में मदद करता है।

ज्यादा ठंडा पानी न पीएं...

गर्मी के मौसम का सबसे ज्यादा प्रभाव शरीर पर पड़ता है और हम इसे ठंडा रखने के लिए कई उपाय भी करते हैं. ठंडा पानी पीना सबसे सरल उपाय होता है लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी यह आदत आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकती है। ठंडा पानी भोजन की पाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है क्योंकि इससे रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इससे पाचन की प्रक्रिया धीमी पड़ने से खाना ठीक से नहीं पचता और हमें इसके पोषक तत्व भी नहीं मिल पाते। बर्फ का पानी या तेज ठंडा पानी पीने से हृदय की गति कम हो जाती है। ठंडा पानी वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करता है। वेगस तंत्रिका 10वीं कपाल तंत्रिका है और यह शरीर के स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर के अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करती है। वेगस तंत्रिका हृदय की गति को कम करने में मध्यस्थता करती है और ठंडा पानी इस तंत्रिका को उत्तेजित करता है जिसके कारण हृदय की गति कम हो जाती है।

प्लास्टिक कचरा गलियों-सड़कों-खेतों से लेकर नदियों और समुद्रों तक में यह प्रवाहित हो रहा है। आप धरती के किसी भी कोने में चले जाएं प्लास्टिक कचरा जरूर दिखेगा। समुद्रों में जिस तरह से प्लास्टिक कचरा बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए यह आशंका प्रबल हो रही है कि वर्ष 2050 तक समुद्र में यह इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मछलियों से ज्यादा तादाद में प्लास्टिक कचरा मौजूद होगा। इससे निबटने के लिए वैज्ञानिक पिछले कुछ दशकों से गंभीर प्रयासों में जुटे हैं और हाल ही में इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्योटो यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम एक बार कचरे के ढेरों में कुछ उम्मीदें तलाश रही थी। उन्होंने प्लास्टिक को कुतरनेवाले कुछ माइक्रोब देखे। करीब 250 सैंपल्स पर पांच वर्षों तक शोध करने के बाद उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को अलग किया, जो पीईटी यानी पॉली-इथिलीन टेरेफ्थालेट में जीवित रह सकते हैं। दरअसल, 'पीईटी' एक कॉमन प्लास्टिक है, जिसका इस्तेमाल बोतलों और अनेक सिंथेटिक कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। प्लास्टिक खानेवाले माइक्रोब्स का धरती पर अस्तित्व कई वर्षों पहले ही खोज लिया गया था। लेकिन, हालिया खोजी गई चीजों में कुछ महत्वपूर्ण फर्क पाये गये हैं। जैसे एक शोध में यह साबित हुआ है कि इस कार्य के लिए उपयोगी माइक्रोब्स को आसानी से पैदा किया जा सकता है।

एंजाइम की भी पहचान

वैज्ञानिकों ने 'आइडियोनेला सेकेनसिस' नामक यह एंजाइम की भी पहचान की है जो 'पीइटी' को नष्ट करने में सक्षम पाया गया है। सभी जीवित चीजों में एंजाइम्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल जरूरी केमिकल रिएक्शंस को गति देना होता है। कुछ एंजाइम्स हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इन जरूरी एंजाइम्स के बिना शरीर कुछ खास प्रकार के भोजन से पोषक चीजें नहीं हासिल कर सकता है। उदाहरण के तौर पर लैक्टोज नहीं पचा पाने वाले लोगों में एंजाइम नहीं होते, जो डेयरी उत्पादों में पाये जोने वाले लैक्टोज शुगर को तोड़ते हैं। कोई भी इन्सान सेल्यूलोज नहीं पचा सकता, जबकि माइक्रोब्स ऐसा कर सकते हैं। 'आइडियोनेला सेकेनसिस' में कुछ ऐसे सक्षम एंजाइम पाये गये हैं, जिन्हें बैक्टीरिया पर्यावरण में पैदा करते हैं। क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया के डीएनए में जीन की पहचान की है, जो पीईटी को पचानेवाले एंजाइम के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार वे ज्यादा से ज्यादा एंजाइम बनाने में सक्षम पाये गये हैं और ये दर्शाते हैं कि महज ये एंजाइम ही इन पीईटी को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं।

वास्तविक रिसाइकलिंग

इस शोध ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग और परिशोधन का एक नया नजरिया दिया है। मौजूदा समय में अधिकांश प्लास्टिक बोतलों को वास्तविकता में रिसाइकिल नहीं किया जाता है। इन्हें पिघला कर और कुछ सुधार करके प्लास्टिक के कठोर उत्पाद बनाये जाते हैं। लेकिन पैकेजिंग कंपनियां ज्यादातर फ्रेश प्लास्टिक का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें पेट्रोलियम पदार्थों से हासिल होनेवाले रसायनों से बनाया जाता है। पीईटी-डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ने ही प्लास्टिक के रिसाइकल की वास्तविक राह तैयार की है। कूड़े-कचरे के साथ मिला कर इनके जरिये सभी प्रकार के प्लास्टिक बोतलों और अन्य आइटम्स को वास्तविक रूप से खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार इन घातक रसायनों से आसानी से निबटा जा सकता है। साथ ही वास्तविक रिसाइकलिंग सिस्टम के जरिये फ्रेश प्लास्टिक बनाया जा सकता है।

प्लास्टिक खाने वाले वर्म्स

वैज्ञानिकों ने पशुओं की आंत में पाये जानेवाले एक ऐसे बैक्टीरिया की भी पहचान की है, जिसे प्लास्टिक को जैविक तरीके से खत्म करने में कामयाब पाया गया है । इससे पर्यावरण को प्लास्टिक के घातक असर से बचाया जा सकेगा। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और चीन की बेहांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसे मीलवर्म की तलाश की है, जो अनेक प्रकार के पॉलिस्टिरीन और स्टाइरोफोम को खाने और उसे पचाने में सक्षम पाये गये हैं। इन वर्म्स की आंत में प्लास्टिक जैविक तरीके से पच जाता है और इसका पूरी तरह से अपघटन हो जाता है। इस शोध से प्लास्टिक से पैदा होने वाली वैश्विक समस्याओं को खत्म करने को एक नयी दिशा मिलने की उम्मीद जगी है।

पानी में घुलने वाला प्लास्टिक

इटली की एक कंपनी ऐसा प्लास्टिक बना रही है, जो पानी में घुल सकता है। यह कंपनी चुकंदर से निकलने वाले कचरे से प्लास्टिक बनाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि चुकंदर के उत्पादन से निकलने वाले बाइ-प्रोडक्ट से बनने वाला प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों से बनने वाले प्लास्टिक पर निर्भरता को कम करने में कामयाबी मिल सकती है। इटली की एक छोटी कंपनी 'बायो ऑन' जैव प्लास्टिक के क्षेत्र में नवीनतम प्रयास का प्रतिनिधित्व कर रही है। इटली के शहर मिनेर्बियो में सबसे बड़ी चीनी उत्पादक कंपनी 'को प्रो बी' चुकंदन से चीनी बनाती है। चुकंदर से चीनी बनने के बाद यह कंपनी कचरे के तौर पर जिन चीजों को फेंक देती है, 'बायो ऑन' उसी से प्लास्टिक का निर्माण करती है।

बैक्टीरिया कुतरेंगे बोतल

वैज्ञानिकों ने ऐसे बैक्टीरिया तैयार किये हैं, जो प्लास्टिक कचरे को खत्म करेंगे। शुरू में इन्हें रिसाइकलिंग सेंटर में कचरे के ढेरों में डाला जाएगा, जहां ये डंप किये गये प्लास्टिक बोतलों को कुतरने का काम करेंगे। हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है और विकसित किये गये बैक्टीरिया को इस कार्य के लिए उपयुक्त पाया गया है। दरअसल, प्लास्टिक को मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों से निकलने वाले कृत्रिम रेजिन से बनाया जाता है। रेजिन में अमोनिया और बेंजीन को मिला कर प्लास्टिक के मोनोमर बनाये जाते हैं। इसमें क्लोरीन, फ्लोरिन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के अणु होते हैं। लंबे समय तक अपघटित न होने के अलावा प्लास्टिक अनेक अन्य प्रभाव छोड़ता है, जो इनसान की सेहत के लिए हानिकारक हैं।

फिल्मों में तकनीक का ओवरडोज...

63वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा हो चुकी है। हॉलीवुड की तरह अब बॉलीवुड की फिल्मों में भी तकनीक का कमाल देखा जा सकता है। किसी फिल्म में यह वाकई कमाल लगता है तो कहीं-कहीं ओवरडोज भी महसूस होता है। कहानी की मांग के बिना जबरन ठूंसा गया यह ओवरडोज फिल्म को फ्लॉप भी करा देता है। इस बारे में पिछले कई साल से फिल्म टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे तन्मय मसूरकर कहते हैं कि हम फिल्म टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निरंतर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह तो फिल्मकारों की जिम्मेदारी है कि वे उसका कितना सटीक उपयोग करते हैं। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि फिल्म निर्माण में साउंड से लेकर स्पेशल इफेक्ट्स तक हर टेक्नोलॉजी एक सही सब्जेक्ट की मांग करती है। फिल्म के सब्जेक्ट में बेवजह इसका इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है।

सब्जेक्ट की मांग: बात वाजिब है। इसके लिए हॉलीवुड फिल्मों का अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है। वहां ज्यादातर फिल्में ही ऐसी बनती हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग की पूरी संभावना रहती है। और जहां सब्जेक्ट इस बात की डिमांड नहीं करता, वहां के फिल्मकार इस बात से साफ बचते हैं। इसके लिए टाइटैनिक का एक उदाहरण देना ही काफी होगा। इस तीन घंटे से ज्यादा लंबी रोमांटिक फिल्म के सब्जेक्ट में रोमांस इस कदर भरा हुआ है कि इसमें फिल्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फइसके कैनवस को विस्तृत रंग देता है। भारतीय फिल्मकारों को भी इसी तरह से सोचना चाहिए। बाहुबली में इसका उपयोग दर्शनीय लगता है। पर पीकू में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सिर्फ निरर्थक होगी। क्योंकि पीकू एक सब्जेक्ट बेस्ड फिल्म है।

तकनीक एक हथियार: संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी भी ऐसी फिल्म है, जिसमें वीएफएक्स सहित दूसरी तकनीक का काफी इस्तेमाल किया गया। भंसाली टेक्नोलॉजी के हिमायती हैं। वे कहते हैं कि फिल्म मेकिंग में टेक्नोलॉजी के बढ़ते महत्व से मैं भी इंकार नहीं करता हूं। मगर यह फिल्म के हर सीन की जरूरत के मुताबिक होना चाहिए। बाजीराव मस्तानी के युद्ध दृश्यों में मैंने टेक्नोलॉजी का खुलकर उपयोग किया। पर इसका यह मतलब नहीं है कि लड़ाई के सीन को हमने सिर्फ वीएफएक्स स्टुडियो में फिल्माया है। इसके वॉर सीन की हमने एक महीने तक शूटिंग की थी। क्योंकि मेरा यह मानना है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ फिल्म के सुंदर फिल्माकंन के लिए जरूरी है। वरना फिल्म तो डायरेक्टर का मीडियम होती है। टेक्नोलॉजी तो महज उसके काम का एक हथियार है। स्पेशल इफेक्ट्स तकनीक की मदद से इसके सारे फ्रेम को और ज्यादा भव्य बनाया गया।

पुरानी फिल्में हैं उदाहरण: आज ज्यादातर फिल्मों में ही तकनीक का कमाल देखने को मिल जाता है। हां, छोटे बजट की फिल्में इस तकनीक से थोड़ा बचती हैं, क्योंकि वीएफएक्स और दूसरी तकनीक का इस्तेमाल खर्चीला है। देखा जाये तो फिल्मों के जन्म के साथ ही फिल्म तकनीक को बढ़ावा मिलने लगा था। कभी महबूब खान, के.आसिफ, वी.शांताराम, राज कपूर आदि दिग्गज फिल्मकारों की नजर फिल्म के तकनीकी पक्ष पर भी होती थी। एक बार झनक-झनक पायल बाजे की शूटिंग से पहले वी.शांताराम के छायाकार जी.बालकृष्ण ने एक खास तरह के लेंस का हवाला देते हुए उनसे कहा था कि यदि यह मिल जाए तो अगली फिल्म की शूटिंग में बहुत सुविधा हो जाएगी। वी.शांताराम यानी अण्णा के जेहन में यह बात बैठ गई। उन दिनों वह लंदन जाने वाले थे। लौटते वक्त वह उस लेंस को अपने साथ ले आए थे।

बड़जात्या नहीं लेते सहारा

वर्तमान में ग्लोबल हो चुके फिल्मोद्योग ने समय के साथ ताल मिलाकर तकनीक के हर बदलाव को बखूबी अंजाम देना सीख लिया है। लेकिन फिल्मकार सूरज बड़जात्या तकनीक के ज्यादा गुलाम नहीं हैं। हालांकि उनकी फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' में उन्होंने न चाहते हुए भी इस तकनीक का उपयोग किया है। इस फिल्म के छायाकार वी. मानिकनंदन इससे पहले रा-वन, ओम शांति ओम, मैं हूं ना, ये जवानी है दीवानी जैसी कई बड़ी फिल्मों का छायांकन कर चुके हैं। मानिकनंदन के मुताबिक सूरज उन निर्देशकों से भिन्न हैं जो अपने दृश्यों को संभालने के लिए तकनीक का सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि हम भारतीय छायाकार विदेशी तकनीशियनों से किसी भी मामले में कमतर नहीं हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि ये सारा कमाल हम बहुत सीमित साधन में कर दिखाते हैं।'

कैसी-कैसी तकनीक

डीआई तो सिर्फ एक तकनीक का नाम हुआ। वरना आज फिल्म की शूटिंग के दौरान चिप, वीएफएक्स, क्रोमा, एनीमेशन, ग्रीडी, ऑन लाइन एडिटिंग या स्मोक आदि ढेरों तकनीकी शब्दों को सुनना बेहद रूटीन सा हो गया है। मजेदार बात तो यह है कि ऐसी ढेरों तकनीक ने एक्शन से लेकर म्यूजिक रिकॉर्डिंग तक हर जगह अपनी जगह बना ली है। आज इस तकनीक की मदद से फिल्मों की भव्यता को एक बुलंदी दी जा रही है। स्पेशल इफेक्ट्स के सारे साधन स्टुडियो में उपलब्ध होते हैं।

मिलावटी दूध से कैसे बचें...?

देश के तीन में से दो लोग डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, यूरिया और पेंट वाल दूध पीते हैं। देश में बिकने वाला 68 प्रतिशत दूध देश की खाद्य उत्पाद नियंत्रक संस्था एफएसएसएआई के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता।

देश के 200,000 गांव से दूध एकत्रित करके बेचा जाता है। मिलावटी दूध से बचने का सबसे सटीक तरीका दूध उबालना है, जिससे सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं। पिछले साल अमेरिका सरकार की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2016 में बढ़ती आबादी के अनुपात में दूध की खपत में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ यह 62.75 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। मिलावटी दूध का शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। यूरिया, कॉस्टिक सोडा और इसमें मौजूद फोरमेलिन से गैस्ट्रोएंट्रटिटिस से लेकर इम्पेयरमेंट, दिल के रोग, कैंसर और मौत तक हो सकती है।

पानी की मिलावट

डिटर्जेंट से पाचन तंत्र की गड़बडियां और फूड पॉयजनिंग हो सकती है। उच्च एल्केलाइन से शरीर के तंतु क्षतिग्रस्त और प्रोटीन नष्ट हो सकते हैं। इन खतरों को देखते हुए बचाव जरूरी है। एफएसएसएआई के ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक, दूध में पानी की मिलावट सबसे ज्यादा होती है, जिससे इसकी पौष्टिकता कम हो जाती है। अगर पानी में कीटनाशक और भारी धातुएं मौजूद हों तो ये सेहत के लिए खतरा है। दूध को उबालना इसका हल है।

इसके साथ ही 46 प्रतिशत सैंपल लो सॉलिड नॉट फैट की श्रेणी के पाए गए, जिसकी मुख्य वजह पानी की मिलावट है। गरमी के मौसम में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते स्किमड मिल्क पाउडर के 548 नमूनों में से 477 नमूनों में ग्लूकोज पाया गया। दूध के रख-रखाव और पैकेजिंग के समय साफ-सफाई का ध्यान न रखे जाने की वजह से आस पास प्रयोग हुआ डिटर्जेंट दूध में चला जाता है। कई बार यह जान बूझ कर डाला जाता है। 8 प्रतिशत नमूनों में डिटर्जेंट पाया गया।

इस तरह करें जांच

- **पानी:** ढलान वाली सतह पर दूध की एक बूंद डालें। शुद्ध दूध की बूंद धीरे-धीरे सफेद लकीर छोड़ते हुए जाएगी, जबकि पानी की मिलवाट वाली बूंद बिना कोई निशान छोड़े बह जाएगी।
- **स्टार्च:** लोडीन का टिंक्चर और लोडीन सॉल्यूशन में कुछ बूंदे डालें, अगर वह नीली हो जाएं तो समझे कि वह स्टार्च है।
- **यूरिया:** एक चम्मच दूध को टेस्ट ट्यूब में डालें। उसमें आधा चम्मच सोयाबीन या अरहर का पाउडर डालें। अच्छी तरह से मिला लें। पांच मिनट बाद, एक लाल लिटमस पेपर डालें, आधे मिनट बाद अगर रंग लाल से नीला हो जाए तो दूध में यूरिया है।
- **डिटर्जेंट:** 5 से 10 एमएल दूध को उतने ही पानी में मिला कर हिलाएं। अगर झाग बनता है तो इसमें समझिए डिटर्जेंट है।
- **सिन्थेटिक दूध:** सिन्थेटिक दूध का स्वाद कड़वा होता है, उंगलियों के बीच रगड़ने से साबुन जैसा लगता है और गर्म करने पर पीला हो जाता है। सिन्थेटिक दूध में प्रोटीन की मात्रा है या नहीं, इसकी जांच दवा की दुकान पर मिलने वाली यूरीज स्ट्रिप से की जा सकती है। इसके साथ मिली रंगों की सूची दूध में यूरिया की मात्रा बता देगी।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**